एक साल नई मिसाल

हुआ विकास, बढ़ा विश्वास

॥ सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः ॥

कुम्भ 2019 प्रयागराज

न्यू इण्डिया का सारथी उत्तर प्रदेश

एक वर्ष पूर्व 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। शपथ ग्रहण के बाद प्रेस से रूबरू मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया था कि ''उनकी सरकार युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने और रोजगार के सुगम अवसर दिलाने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करेगी। नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचारविहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ाते हुए संतुलित औद्योगिक विकास एवं ग्रामीणों/किसानों/खेतिहर मजदूरों के विकास के हर स्तर पर प्रयास होंगे और महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए हर संभव कार्य किये जायेंगे।''

मुख्यमंत्री की प्रथम उद्घोषणा अर्थशास्त्र में चाणक्य द्वारा वर्णित शासकीय नीति–

''प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां तु हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितम्।।''

के अनुसार थी और इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के इस ध्येय वाक्य को कार्यशैली में परिवर्तित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में पूरे परिदृश्य को जनता के लिए प्रियकर और हितकर स्वरूप में बदला है। एक वर्ष पूर्व युवाओं में एक दिशाहीनता घर कर गयी थी, युवाओं में यह कुंठा थी कि उनके साथ भेदभाव होता है। समाज में शांति एवं सुरक्षा के प्रति घोर चिंता थी। नई पीढ़ी की निर्माणशालाओं में यानी शिक्षण संस्थाओं में पठन–पाठन के उपयुक्त माहौल का अभाव था, परीक्षाओं की व्यवस्था लचर थी। प्रदेश में बिजली वैसे ही कम थी और जो थी, उसके वितरण में वी.आई.पी. और गैर वी.आई.पी. क्षेत्रवार भेदभाव किया जाता था। रोजगार पैदा करने वाले निजी उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश अपेक्षानुसार नहीं हो रहा था। बुन्देलखण्ड में लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे ।

INVESTORS SUMMIT 2018

किसान कर्ज के बोझ से बदहाल थे और पूरे प्रदेश में निराशा व हताशा छा गयी थी। इस दिशाहीन – निराशाजनक परिदृश्य में परिवर्तन और विकास की एक बड़ी जनाकांक्षा के साथ नई सरकार गठित हुई थी, इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश को नकारात्मक छवि से उबारना था। साथ ही देश–विदेश में खासतौर पर उद्योग जगत में कम से कम समय में यू0पी0 को सकारात्मक, सुरक्षित और परिणामदायी प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करना भी अहम कार्य था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थिति को भलीभांति भांप लिया था, इसलिए बिना समय गंवाये राज्य को निराशा के वातावरण से निकालने, समाज में शांति एवं सुरक्षा का माहौल पैदा करने और युवाओं, किसानों, उद्यमियों तथा अन्य आम लोगों को एक आशाजनक, सकारात्मक परिवेश देने का कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए

राज्य सरकार ने अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में ही राज्य के 86 लाख से अधिक किसानों के फसली ऋण मोचन का फैसला लेते हुए 36 हजार करोड़ रू० का व्यय करते हुए छोटे किसानों को बैंकों के कर्ज से उबारने का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ई–टेंडरिंग प्रणाली लागू की, जिससे ठेकों और सरकारी कार्यों में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लग सके। स्कूली छात्राओं और युवतियों को शोहदों की छेड़छाड़ से बचाने के लिए 'एंटी रोमियो स्क्वैड' गठित कर महिलाओं में सुरक्षा की भावना भरी। इसके बाद अगले छह माह में कानून–व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए अनेक कड़े कदम उठाये गये और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध मुहिम चलायी गयी। उन्हें स्पष्ट संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की स्पष्ट सोच और नीयत की बदौलत आज राज्य में महिलाओं, दलितों सहित सभी वर्गों के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामाजिक अमन–चैन के वातावरण ने उत्तर प्रदेश को एक नये रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है।

महज एक वर्ष में राज्य में पूंजी निवेश के प्रस्तावों का एक अभूतपूर्व रिकार्ड स्थापित हुआ है। 21 एवं 22 फरवरी को सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के

पूंजी निवेश के प्रस्ताव देश के चोटी के उद्योगपतियों से प्राप्त हुए। पूंजी निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दिया है। इसे प्राप्त करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार भी किया है। लगभग पाँच लाख करोड़ पूंजी निवेश के प्रस्ताव का रिकार्ड और इतना विशाल लक्ष्य उत्तर प्रदेश को मिलना सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट सोच, ईमानदार छवि और सुधरती कानून व्यवस्था के कारण संभव हुआ है।

सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है, इसका प्रमाण है आन लाइन 'सिंगल विंडो' सिस्टम जिसका अनुश्रवण स्वयं मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। दरअसल प्रदेश सरकार का संकल्प राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रूपये के बजट आकार से आगे राज्य की वास्तविक क्षमता तक ले जाने का है। इसमें पूंजी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना ज्यादा पूंजी निवेश होगा, उतनी ही अधिक आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और विकास की गति तेज होगी। इसके परिणामस्वरूप युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार भी मिलेंगे। राज्य की बदलती आर्थिक तस्वीर का पूरा लाभ हमारे राज्य के युवा उठा पायें, इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना एक अपरिहार्य कदम है। इसी के मद्देनजर सरकार ने शैक्षणिक माहौल बदलने के लिए न केवल शैक्षणिक कैलेण्डर जारी किया, बल्कि अनावश्यक छुट्टियों को निरस्त कर पढ़ाई के दिवसों में भी वृद्धि की और नकल पर नकेल लगायी। सरकार के इन प्रयासों को आम जनता ने खुले मन से सराहा है।

बीते एक वर्ष में श्रावण झूला मेला, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईदुज्जुहा, नवरात्रि, विजयदशमी, मोहर्रम, दीपावली, छठ पूजा, चेहल्लुम, बारावफात, क्रिसमस, मकर–संक्रांति, बसंत–पंचमी और होली के पर्व सांप्रदायिक सद्भाव के साथ शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए।

विकास के दो प्रमुख कारक सड़क और बिजली क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में भी अच्छे परिणाम हासिल किये हैं। नई सरकार के गठन के समय राज्य में सड़कों की हालत खस्ता थी। इसीलिए प्रथम सौ दिनों में बरसात के पूर्व लगभग 101000 हजार कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया और बिजली उपलब्धता और आपूर्ति की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय भेदभाव को दूर किया गया। क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे तहसील मुख्यालय में 20 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर वर्तमान सरकार ने इस समस्या का भी निराकरण किया और 48 घण्टों में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ग्रामीणों एवं किसानों का भरोसा जीता।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत 1.71 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत कुल 15781 विशेष शिविर आयोजित कर 32 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। सरकार ने इस वर्ष 7 हजार असेवित गांवों को ट्रांसपोर्ट सुविधा से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। तहसील और ब्लाक मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार है। लखनऊ –बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 92 प्रतिशत पूरा हो गया है । बुन्देलखण्ड को आगरा एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर

लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए प्रथम चरण में धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

राज्य की युवा शक्ति को हताशा और दिशाहीनता से निकालने के लिए राज्य सरकार ने रोजगार हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भेदभाव समाप्त कर एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करायी है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली को सुधारा गया है, जिससे युवाओं में न्याय और निष्पक्षता के प्रति गहरा विश्वास पैदा हुआ है। इसके साथ ही ''जिस काम का पैसा–उसी काम में खर्च हो'' की नीति को कड़ाई से लागू किया गया है। विकास के पैसे में छीजन न होने पाये, यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन सब उपायों से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं आय दोनों में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को विकासशील और समृद्ध बनाने के लिए एग्रो –फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैण्डलूम –टैक्सटाइल, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग, आई0टी0/आई.टी.ई.एस. एण्ड स्टार्टअप, इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग, फिल्म, टूरिज्म, सिविल एविएशन और रिन्यूएबल एनर्जी को केन्द्र बिन्दु में रखा है।

सरकार ने इस वर्ष एक नायाब प्रयोग करते हुए प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद जैसे हस्तशिल्प अथवा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए "एक जनपद–एक उत्पाद" नाम से अभिनव योजना प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत सम्बंधित जनपद के प्रत्येक उत्पाद के लिए मार्केटिंग, तकनीकी उन्नयन, कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण तथा आसान ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके लिए सुदृढ़ कानून– व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधा (बिजली, सड़क, परिवहन, सिंचाई) सुनिश्चित करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर भी ध्यान बनाए रखा है। पहली बार किसी सरकार ने सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, विमानन, निर्यात–प्रोत्साहन, स्टार्ट अप और खनन नीति की घोषणा बजट में ही कर दी है। बजट घाटा भी पिछली बार से कम 2.96 प्रतिशत नियंत्रित रखा है, जिस कारण नये टैक्स नहीं लगाये गये। सरकार की इस नयी कार्यशैली का स्वागत ग्लोबल टैक्स पेयर ट्रस्ट के चयेरमैन ने भी किया है। संभवतः इन्हीं कारणों से यू0पी0 की नकारात्मक छवि बदली और नकारात्मकता के कुहासे से उबरकर प्रदेश सकारात्मकता के नये उजाले की ओर बढ़ सका है। अचरज नहीं कि उत्तर प्रदेश विकास की नई मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो रहा है।

सबको सुरक्षा – भय मुक्त समाज

गृह विभाग/पुलिस

अपराध व अपराधियों के प्रति जीरों टॉलरेन्स एवं हस्तक्षेप रहित पुलिसिंग से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। श्रावण झूला मेला, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईद–उल–जुहा, नवरात्रि, विजयदशमी, मोहर्रम, दीपावली, छठपूजा, चेहल्लुम, बारावफात, क्रिसमस, मकर संक्राति, बसन्त पंचमी तथा होली पर्व शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी सद्भाव के साथ संपन्न हुए। सामाजिक अमन–चैन के वातावरण ने उत्तर प्रदेश को एक नये रूप में प्रस्तुत किया है, परिणामस्वरूप राज्य में पूँजी निवेश के प्रस्ताव का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

- प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 5.70%, हत्या में 7.35% रोड होल्डअप में 100%, फिरौती में 13.21%. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41%, आगजनी में 29.73% की कमी।
- पुलिस और अपराधियों के बीच 1418 मुठभेड़। 3316 अपराधी गिरफ्तार। 366 अपराधी घायल तथा 45 अपराधी मारे गए।
- गत वर्ष की तुलना में गुण्डा एक्ट से 0.19%, गैंगस्टर एक्ट। 2.15%, एनएसए में 5.00%, जुआ अधि0 में 13.17% एवं एनडीपीएस अधि0 में 12.88% की अधिक कार्यवाही।
- अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के कारण 5409 अपराधियों द्वारा स्वयं जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण।
- एन्टी–रोमियो दस्तों द्वारा 26,36,070 व्यक्तियों की चेकिंग, 1987 अभियोग पंजीकृत 3,418 व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं 11,94,921 व्यक्तियों को चेतावनी।
- 4870 आरक्षी एवं उपनिरीक्षकों का सेवायोजन। आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के 86,954 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित।
- यूपी 100 का औसतन रिस्पान्स टाइम 14.15 मिनट रहा ।
- 1531 भू–माफियाओं के विरूद्ध 2596 अभियोग पंजीकृत, 1922 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 460 हाजिर अदालत, 6 कुर्की तथा 7.45 करोड़ रू की अवैध सम्पत्ति की जब्ती।

- फुट पेट्रोलिंग में 1,59,927 संदिग्ध लोग हिरासत में लिये गये तथा 88,093 अभियोग पंजीकृत कर 95,964 अभियुक्त गिरफ्तार किए गये।
- अपराधों को शत–प्रतिशत दर्ज करने के सख्त निर्देश।
- वूमेन पॉवर लाइन 1090 के माध्यम से 1,77,522 शिकायतों का समाधान।
- एटीएस द्वारा आतंकवाद से जुड़े 16 व्यक्तियों की गिरफ़्तारी।
- आमजन की सुविधा के लिये यूपी–100 सेवा के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा का एकीकरण।
- कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते को 950 रूपये से बढ़ाकर 1350 रूपये, मुख्य आरक्षी व आरक्षियों के आहार भत्ते को 1050 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये तथा उपनिरीक्षक निरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग के लिए इस भत्ते को 900 रूपये से बढ़ाकर 1200 रूपये किया गया।
- जन शिकायतों के यू.पी. पुलिस के ट्विट्र सेवा से कुल 438826 ट्वीट प्राप्त हुए, जिसमें कार्यवाही योग्य कुल ट्वीट 69925 में से 69,829 ट्वीट्स निस्तारित ।
- ट्विटर के माध्यम से प्राप्त एफआईआर पंजीकरण के प्रकारणों में कुल 460 एफ.आई.आर पंजीकृत।
- लखनऊ शहर में स्थापित "दृष्टि" कन्ट्रोल रूम में 70 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के अतिरिक्त 85 रिलायन्स जियो के टावरों पर 517 सीसीटीवी कैमरे स्थापित।
- आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) को सुदृढ़ करने के लिए 316 पद सृजित।
- आनलाइन परीक्षा के माध्यम से पारदर्शी भर्ती की शुरूआत। 3307 उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती हेतु आनलाइन लिखित परीक्षा सम्पन्न।
- प्रदेश के दो थाने क्रमशः थाना–गुडम्बा, जनपद लखनऊ तथा थाना–घिरोर, जनपद मैनपुरी को पूरे देश के 10 सर्वोत्तम थानों में चयनित थाना गुडम्बा को तीसरा तथा थाना–घिरोर को सातवाँ स्थान ।

पुलिस के शहीदों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रू तथा उनके माता पिता को दी जाने वाली धनराशि को 5 लाख रू से बढ़ाकर 10 रू लाख किया गया।

चमकेगी हर सड़क, दौड़ेगा प्रदेश

लोक निर्माण

अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक प्रदेश की लगभग 1,07,000 कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 1,01,000 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। लोकनिर्माण विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 85,160 कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 84,990 कि0मी0 से अधिक सड़कें गड्ढामुक्त की गयी।

1048 कि0मी0 की 110 सड़कों/ परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण

महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण

1. जनपद श्रावस्ती में नानपारा – शंकरपुर – लालपुर–हुजूरपुर मार्ग (लम्बाई 22 कि0मी0)।
2. जनपद गोण्डा में दर्जीकुआं –मनकापुर – बभनान मार्ग (लम्बाई 53 कि0मी0)।
3. जनपद गोण्डा में मनकापुर– मसकनवा– बभनान मार्ग (लम्बाई 30 कि0मी0)।
4. जनपद देवरिया में देवरिया–रूद्रपुर – कहर कोल मार्ग (लम्बाई 33 कि0मी0)।
5. जनपद बस्ती में परसा–परसरामपुर मार्ग (लम्बाई 14 कि0मी0)।
6. जनपद कुशीनगर में गोरखपुर – पिपराईच–कप्तानगंज–नौरंगिया मार्ग (लम्बाई 19 कि0मी0)।
7. जनपद कौशाम्बी में मनौरी – सरायअकिल–कौशाम्बी मार्ग (लम्बाई 16 कि0मी0)।
8. जनपद पीलीभीत में पूरनपुर खटीमा मार्ग (लम्बाई 27.00 कि0मी0)
9. जनपद अमेठी में अमेठी– दुर्गापुर मार्ग (लम्बाई 26.00 कि0मी0)

86 दीर्घ सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर, 18 सेतु अप्रोच मार्ग सहित पूर्ण

महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण

1. जनपद आगरा में यमुना नदी / रूनकता के पास ग्राम अकबरा और नेरा के मध्य नेरा घाट पर सेतु का निर्माण।

❖ इलाहाबाद में टोन्स नदी, चित्रकूट में पहाड़ी से अरछा बरेठी मार्ग और ग्राम लोहदा से औहदा, आगरा में खारी नदी/अकोला बेरी मार्ग पर घासी बाबा मन्दिर, उन्नाव में सई नदी रामेश्वर मंदिर के पास, उन्नाव में बांगरमऊ– बलुआ घाट, रामपुर में सैजनी नदी द्विजोड़ पर, मुरादाबाद सम्भल मार्ग पर सोत नदी, लखीमपुर में चौका नदी में मझहा पटना मार्ग पर सेतु का निर्माण।

❖ गोरखपुर में आमी नदी/कटाई टीकर जोगियाखोर मार्ग, बरेली में ब्लाक शेरगढ़ के अन्तर्गत मदनापुर के निकट बहगुल नदी, बरेली में ग्राम चका चौडेरा मुड़िया नबीबक्श मार्ग पर, गोरखपुर में बड़हलगंज असवानपार रूद्रपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण।

❖ झांसी में केन नदी/चार लेन बाई पास, वाराणसी में गंगा नदी/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेशद्वार के सामने घाट पर रामनगर मार्ग पर और गंगा नदी/धानापुर चहनिया मार्ग के बलुआ घाट सेतु का निर्माण।

❖ बांदा में यमुना नदी/बांदा बहराइच रा0मा0 सं0–13 में पूर्व निर्मित सेतु के पास चिल्ला घाट पर नये पक्के सेतु का निर्माण।

जनपद गोरखपुर में कटाई टीकर जोगियाकोल मार्ग पर आमी नदी सेतु पर पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण

40 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर, 12 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण

महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण

❖ अलीगढ़ में गभाना बरौली मार्ग से पोथी पिपलोठ वाया लालपुर मार्ग, मऊ में पुनापार–इमिलिया मार्ग, बलिया में सीसोटार में भागड़ नाला, ग्राम पंचायत निपनिया के पूरब नाला, असना (सोनूपार) सम्पर्क मार्ग में बेहरा नाला, कानपुर में नोन नदी/चौबेपुर मरखरा मार्ग पर सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

❖ रामपुर में विलासपुर मिलक खानम–स्वार माग, बिजनौर में नूरपुर–स्योहारा ठाकुर द्वारा मार्ग, बिजनौर में ग्राम भरौरा हेतु छोईया नदी पर, गाजीपुर के ग्रामसभा मुसरदेवा नाले, सोनभद्र में ग्राम पूर्वी देवहार में पुल, पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण ।

41 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर, 09 रेल उपरिगामी सेतु अप्रोच मार्ग सहित पूर्ण :

महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण

1. जनपद संत कबीरनगर में खलीला बाद–गोरखपुर सेक्शन पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण।
2. जनपद कानपुर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु निर्माण।
3. उन्नाव में रेलवे स्टेशन के निकट लखनऊ–कानपुर रेल मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
4. जनपद हाथरस में टूण्डला गाजियाबाद पर दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।
5. जनपद हाथरस में सासनी जलेसर मार्ग दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
6. जनपद जे0पी0 नगर (अमरोहा) में अमरोहा–अटारसी मार्ग पर अमरोहा – काफूरपुर के रेल सेक्शन दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
7. जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद – हरिद्वार मार्ग पर अगवानपुर पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
8. जनपद वाराणसी में वाराणसी– मण्डुआडीह रेलवे स्टेशन यार्ड में रेलवे सम्पार सं0–3ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
9. जनपद फतेहपुर में खागा स्टेशन के समीप क्रासिंग सं0–37 ए पर इलाहाबाद कानपुर सेक्शन में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

केन्द्रीय मार्ग निधि योजना–

- योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य को रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति ।
- प्रथम चरण में 117 कार्यों रू0 3015.77 करोड़ (लम्बाई 1797.39 किमी0), की स्वीकृति प्राप्त।
- द्वितीय चरण में 164 कार्य रू0 4111 करोड़ (लम्बाई 2569 किमी0) के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित।

753 मार्गों का 04 लेन, चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं बाईपास निर्माण (लं. 10112 कि0मी0, लागत रू0 23999 करोड़) प्रगति पर।

कुम्भ 2019 के 93 कार्यों हेतु रू0 758 करोड़ की परियोजनाएं। प्रथम चरण में 4 कार्यों हेतु रू0 110 करोड़ स्वीकृत।

नेशनल हाईवे की घोषणा

प्रदेश के 52 मार्ग (लम्बाई 3975 कि0मी0) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित। दिल्ली–सहारनपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित। 51 अतिरिक्त मार्गों (लम्बाई 4523 किमी0) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित। प्रथम चरण में 25 मार्ग (लम्बाई 2493 किमी0) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए चयनित।

(ii) नवीनतम तकनीक द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित मार्ग निर्माणाधीन।

- उन्नाव में लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग (लागत रू0 3.77 करोड़)।
- उन्नाव में दोस्तीनगर बाईपास (लागत रू0 4.97 करोड़)।
- हरदोई में पलिया–लखनऊ मार्ग (लागत रू0 277 करोड़)।
- सीतापुर में बिलराया–पनवारी मार्ग (लागत रू0 342 करोड़)।
- हरदोई में हरदोई–लखनऊ मार्ग (लागत रू0 170 करोड़)।
- लखनऊ में पलिया–लखनऊ राज्य मार्ग (लागत रू0 202 करोड़)।
- उन्नाव में सण्डीला – रसूलाबाद–चकलबंशी मार्ग (लागत रू0 19 करोड़)।
- उन्नाव में उन्नाव–शुक्लागंज चार लेन मार्ग (लागत रू0 102 करोड़)।
- लखनऊ में बिजनौर–सिसैण्डी–मौरावां मार्ग (लागत रू0 31 करोड़)।
- सीतापुर में लखनऊ–कुर्सी– महमूदाबाद मार्ग (लागत रू0 4करोड़)।
- लखनऊ में लखनऊ–वाराणसी (तेलीबाग मार्ग) (लागत रू0 33 करोड़)।
- लखनऊ शहर में पिकअप तिराहे से शहीद पथ तक मार्ग (लागत रू0 21 करोड़)।
- खीरी में गोला–अलीगंज मार्ग (लागत रू0 16 करोड़)।
- कानपुर देहात में सिकन्दरा–झीझक – रसूलाबाद मार्ग (लागत रू0 16 करोड़)।
- जौनपुर में लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग (लागत रू0 136 करोड़)।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम

- दिसम्बर 2017 तक लगभग रू0 889 करोड़ के कार्य सम्पन्न।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रू 4500 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- 45 विभागों के कुल 1048 कार्य प्रगति में तथा अन्य प्रदेशों में कुल 684 कार्य प्रगति पर।

रोड सेफ्टी

यातायात सुरक्षा की दृष्टि से समस्त मार्गों पर **ब्लैक स्पॉट** चिह्नित, एक से दो वर्ष के अन्दर ब्लैक स्पॉट मुक्त किये जाने का कार्य प्रारम्भ।

टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई–टेंडरिंग की व्यवस्था लागू। विभागीय कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा हेतु **''सी.एम. डैश बोर्ड''** के नाम से पोर्टल विकसित।

हेल्पलाईन

सामान्य जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाईन नं0 प्रारम्भ

1800 121 5707

हौसला बढ़ाते नवाचार

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की वर्ष 2017 परीक्षा में प्रदेश में टॉप करने वाले 24 मेधावियों के घरों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु नवनिर्माण/मरम्मत के (लम्बाई 24 किमी0 लागत लगभग रू0 748 लाख) कार्य स्वीकृत।

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार

माध्यमिक शिक्षा

- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परिक्षाएं नकलविहीन एवं शुचितापूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न।
- प्रथम बार परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था।
- प्रथम बार 50 जनपदों में क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था।
- विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था ।
- प्रथम बार वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था।
- कक्षा–9 व 11 के छात्र/छात्राओं का आधार लिंक ऑन लाइन अग्रिम पंजीकरण।
- **गुणवत्ता सुधार**
- शैक्षिक सत्र 2018–19 से एन0सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली के अनुरूप हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम/ पाठ्यपुस्तकों का प्रचलन।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवम् कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 1–आटोमोबाइल, 2–रिटेल, 3–सिक्योरिटी, 4–आई0टी0, 5–हेल्थ एण्ड वेलनेस ट्रेड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के पाठ्यक्रम में शामिल।
- न्यूनतम 220 शैक्षिक कार्यदिवस निर्धारित।
- कक्षा–9 के कमजोर छात्र/छात्राओं को अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित में एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण।
- पहली बार 147 मेधावी छात्र–छात्राओं का एक लाख रूपये की धनराशि, एक टैबलेट व प्रशस्ति पत्र से सम्मान।
- हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने हेतु रू0 2000 (दो हजार रूपये) प्रतिमाह/प्रति छात्र की दर

से पं0 दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति।

शिक्षकों की व्यवस्था

- ❖ राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के चयन की व्यवस्था उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से।
- ❖ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पारदर्शी, चयन हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, इलाहाबाद का पुनर्गठन।

बालिका शिक्षा

- ❖ समस्त राजकीय इण्टर कालेजों (बालक) में सह–शिक्षा की व्यवस्था।

उच्च शिक्षा की ऊंची उड़ान

- ❖ स्नातक तक सभी कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा।
- ❖ सभी शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा तथा प्रत्येक छात्र व स्टाफ को प्रति माह 1.5 जी.बी. निःशुल्क सुविधा देने का अनुबन्ध पत्र Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) के साथ हस्ताक्षरित।
- ❖ राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त 843 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ।
- ❖ राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्यों के सभी पदों पर नियुक्ति। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में उच्चतर 870 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति।
- ❖ रू0 25.00 लाख की दर से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु कुल रू0 3.50 करोड़ की धनराशि 14 राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित।

खूब पढ़ो–आगे बढ़ो

बेसिक शिक्षा

- कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,837 विद्यालयों में इस वर्ष कुल 1,54,22,047 बच्चों का दाखिला कराया गया।
- समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का शत–प्रतिशत वितरण।
- परिषदीय तथा राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1–8 के लगभग 1.67 करोड़ छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म।
- पहली बार परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क बैग, जूता एवं मोजा वितरित। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को इस वर्ष स्वेटर भी दिए गए हैं।
- परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के जनपदस्तरीय स्थानान्तरण की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ। निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी प्रारम्भ।
- परिषदीय 5865 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क–बेंच क्रय करने हेतु धनराशि आवंटित।

पुरातन चिकित्सा-पद्धति का पुनरस्थापन

आयुष

- ❖ लखनऊ में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2017) आयोजित किया गया, जिसमें मा. प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा ब्लाक मुख्यालयों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम लोगों में योग के प्रति जागरूकता तथा जन सहभागिता सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य में सफल रहा।
- ❖ प्रदेश के समस्त जनपदों में योगा वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं।
- ❖ औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु मेडिसिन मैनेजमेन्ट साफ्टवेयर प्रारम्भ।
- ❖ नवसृजित राजकीय गोरखपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ।
- ❖ राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी के नवीन चिकित्सालय भवन, प्रशासनिक भवन एवं महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण।
- ❖ कौशाम्बी, सोनभद्र, जालौन, संतकबीरनगर, सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, अमेठी, कानपुर देहात एवं बलिया हेतु प्रत्येक में 50 बेड का एकीकृत आयुष चिकित्सालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- ❖ राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, वाराणसी में तीन विषयों यथा—रोग निदान, शल्य तंत्र तथा संस्कृति एवं सिद्धान्त में प्रत्येक विषय में 05 सीट (कुल 15 सीटों) पर पी.जी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति।
- ❖ राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में धनवन्तरि छात्रावास का निर्माण प्रारम्भ।

स्वस्थ हो घर परिवार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- **6 मंडल स्तरीय एवं 4 जिला स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा प्रारम्भ। 150 एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बूलेंस सेवा प्रारम्भ।**
- ओ0पी0डी0 में कुल 50,15,942 रोगियों की सेवा की गयी।
- सघन मिशन इन्द्रधनुष योजना में अभियान चलाकर 77 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण।
- समस्त जनपदों हेतु कंडीशनल मैटरनिटी बैनिफिट कार्यक्रम–प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन।
- 1407 चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के साक्षात्कार सम्पन्न। 373 चिकित्साधिकारी एवं 98 विशेषज्ञों का चयन ।
- फ्री डायग्नोस्टिक इनिशियेटिव के अन्तर्गत 61 जनपदों में से 12 जनपदों में सेवा प्रारंभ तथा शेष जनपदों में कार्यवाही प्रगति पर।
- आयुष पद्धतियों से 1,24,09,202 रोगियों का इलाज किया गया।
- 1662 चिकित्सकों की तैनाती। इसके अतिरिक्त वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयनित 94 चिकित्सकों की तैनाती, जिनमें से 34 विशेषज्ञ हैं।

18 मण्डलीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाओं हेतु सेवा प्रदाता का चयन करते हुए 06 मण्डल आजमगढ़, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी एवं सहारनपुर में मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों में सेवाएं प्रारम्भ। 18 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया और जिला स्तरीय चिकित्सालायों–जनपद रायबरेली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर एवं कुशीनगर में डायलिसिस सेवाएं प्रारम्भ।

- दन्त शल्य चिकित्सकों के 595 नये पद सृजित।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित जनपदों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को यूनिसेफ, पॉथ संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 के रोकथाम एवं बचाव हेतु वर्ष 2018 के लिए विस्तृत कार्य योजना एवं कैलेन्डर इवेन्ट्स तैयार कर जनपदों को कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य शिविर योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2956 शिविर लगाकर 389009 मरीजों का उपचार। शहरी क्षेत्रों में कुल 724 कैम्प लगाकर 121377 मरीजों का उपचार।
- 68 जनपदों के जिला पुरूष चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित।
- 62 जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में 12 शैय्यायुक्त 76 सिक न्यू बार्न केयर यूनिट स्थापित।
- लिंग चयन/भ्रूण हत्या/अवैध गर्भपात में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मुखबिर योजना प्रारम्भ।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक माह की 09 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सभी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध माह दिसम्बर तक 434124 ए0एन0सी0 जांचे की गयी तथा उच्च जटिलता वाली 36678 गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा

चिकित्सा शिक्षा

- जनपद गोरखपुर में AIIMS की स्थापना हेतु भारत सरकार से एम0ओ0यू0 निष्पादित।
- केन्द्र सरकार द्वारा 08 नये मेडिकल कालेजों को स्वीकृति।
- कानपुर एवं आगरा, मेडिकल कालेज में प्रत्येक में 08 सुपर स्पेशियलिटी विभाग की स्थापना हेतु फण्डिंग।
- राजकीय मेडिकल कालेजों तथा संस्थानों में ई–हास्पिटल योजना चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ।
- शैक्षणिक सत्र 2017–18 में राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 1673 सीटें तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 2550 सीटों पर आवंटन।
- मेडिकल विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं कालेजों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/ एम0डी0/ एम0एस0/

स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम / एम0डी0एस0 / डी0एम0 / एम0सी0एच0 पाठ्यक्रमों की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदेश में ही प्रत्येक स्तर पर 02 वर्षों की अनिवार्य राजकीय सेवा हेतु बाण्ड भराया जायेगा।

- मरीजों को गुणवत्तायुक्त औषधि उचित एवं सस्ते मूल्यों पर प्रदान करने हेतु मेडिकल कालेजों में अमृत फार्मेसी की स्थापना।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एम0डी0 माइक्रोबायोलाजी, एम0सी0एच0 गैस्ट्रो सर्जरी एवं एम0सी0एच0 यूरोलॉजी विभाग के 03 नये पाठ्यक्रम तथा 150 सीटों पर एम0बी0बी0एस0 कोर्स प्रथम बार प्रारम्भ किया गया।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 200 शैय्यायुक्त मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय को एक उत्कृष्ट केन्द्र (सेंटर आफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया गया है।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पक्ष में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा रूपया 473 करोड़ की ऋण की प्रशासकीय स्वीकृति एवं शासकीय गारन्टी जारी। जिससे इमरजेन्सी मेडिसिन, गुर्दा प्रत्यारोपण सेन्टर, लीवर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर एवं रोबोटिक्स सर्जरी विभागों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में किडनी ट्रान्सप्लान्ट की सुविधा।
- के0जी0एम0यू0 में 25 शैय्याओं के बर्न्स एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना का निर्माण कार्य पूर्ण।

सतत् विकास के लिए सौर ऊर्जा

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित।
- वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण।
- सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट लगाये जाने का प्राविधान।
- सोलर पावर परियोजनाओं हेतु ऑन–लाइन एकल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था।
- सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।
- सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट पर 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त रू. 15000 प्रति कि.वाट अधिकतम 30000 रूपया प्रति उपभोक्ता राज्य अनुदान का प्राविधान।

उपलब्धियां

- प्रदेश में अब तक कुल 512 मेगावट की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं स्थापित।
- प्रदेश में अब तक कुल 76.2 मेगावाट की सोलर रूफटाप परियोजनायें स्थपित।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में समस्त विकास खण्डों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु 7850 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना।

रौशन हुआ प्रदेश

ऊर्जा

क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करते हुए प्रदेश के सभी स्थानों पर एक जैसा विद्युत आपूर्ति शिडयूल लागू। शहरों की भॉति ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात में निर्बाध विद्युत आपूर्ति। जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे एवं गॉवों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति।

- वर्ष 2017—18 में माह फरवरी, 2018 तक 55654 मजरों का ऊर्जीकरण ।
- वर्तमान वर्ष 2017—18 में माह फरवरी, 2018 तक 3163689 विद्युत संयोजन निर्गत।
- वर्ष 2016—17 में प्रदेश की पारेषण क्षमता अभिवृद्धि 15000 एम.वी.ए के सापेक्ष फरवरी 2018 तक 16348 एम.वीए. प्राप्त कर उल्लेखनीय वृद्धि।
- वर्ष 2016—17 में औसत विद्युत आपूर्ति 287 मि.यू. प्रतिदिन थी जो 2017—18 में 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ 312 मि.यू प्रतिदिन रिकार्ड की गई।
- वर्ष 2016—17 में पारेषण नेटवर्क की आयात क्षमता (टी.टी.सी) 6600 मेगावाट थी जो फरवरी 2018 में 9200 मेगावाट हो चुकी है और जिसके मार्च 2018 तक 10000 मेगावाट होने की सम्भावना है।
- 111 नये 33/11 के.वी विद्युत उपस्थान ऊर्जीकृत। 384 विद्युत उपस्थान की क्षमता वृद्वि कर 2031 एम0वी0ए0 क्षमता का सृजन। प्रदेश में 11344 नये वितरण परिवर्तक भी स्थापित 10631 अतिभारित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की गयी है।

- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये संयोजन मौके पर ही देने हेतु ई–संयोजन मोबाइल एप्प व्यवस्था लागू।
- लगभग एक लाख कृषकों के निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण सम्भव हो सकेगा।
- 05 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन के लिए इस्टीमेट की प्रथा समाप्त कर आसान किश्तों में विद्युत संयोजन देने के लिये ''सुगम संयोजन योजना'' लागू। नये 03 कनेक्शन की मॉग होने पर एक विद्युत पोल लगाकर विभागीय खर्चे पर विद्युत लाइन का विस्तार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की भॉति शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। इस योजना में 32 लाख परिवारों को विद्युत संयोजन ।

- पहली बार उपभोक्ताओं को स्वयं विद्युत बिल सृजित करने तथा भुगतान इन्टरनेट से करने की सुविधा।
- मोबाइल एप ई–निवारण द्वारा विद्युत बिल एवं आपूर्ति सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा।
- विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया भुगतान में 100 % अधिभार माफी एवं अवैध विद्युत संयोजन को वैध करने हेतु **सर्वदा योजना,** इससे लगभग 20 लाख विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित।
- जनपद हापुड़ में 1000 करोड़ से 765 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, पी0पी0पी0 के आधार पर ऊर्जीकृत। नहटोर (बिजनौर), माट (मथुरा), बांदा, आगरा दक्षिण (आगरा), अटौर (गाजियाबाद), इन्दिरापुरम् (गाजियाबाद) एवं डासना (हापुड़) में 400 के0वी0 उपकेन्द्र कुल 2210रू0 करोड़ की लागत से ऊर्जीकृत।
- चन्दौसी (सम्भल), रनिया (कानपुर देहात), छाता (मथुरा), मोरटी (गाजियाबाद), अमरोहा, जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर), पीलीभीत तथा हापुड़ में कुल 628 करोड़ रूपये लागत से 220 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत।

ग्रामीण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का 48 घंटे में एवं शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में प्रतिस्थापन।

- बिचपुरी (आगरा), दनकौर (गौतमबुद्धनगर), गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़), सलोन (अमेठी), महमूदाबाद (सीतापुर), गभाना (अलीगढ़), ग्वालियर रोड (आगरा), बिन्दवल जयराजपुर (आजमगढ़), बण्डा (शाहजहॉपुर), मवाना रोड (मेरठ), हमीरपुर, पयागपुर (बहराइच), नवाबगंज (गोण्डा), जरी (इलाहाबाद), जलालाबाद (शामली), लालपुर (रामपुर), भोपा (मुजफ्फरनगर), नवाबगंज (बरेली), भूड–II (बुलन्दशहर) तथा बन्नत (शामली) में 132 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र कुल लागत रू0 645 करोड़ से ऊर्जीकृत।

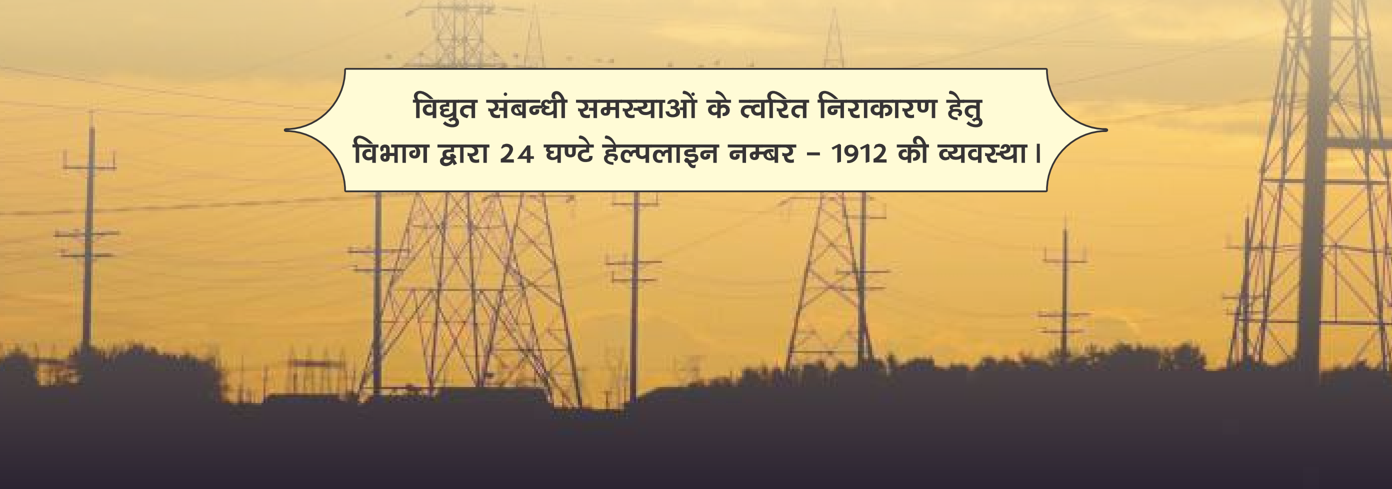

विद्युत संबन्धी समस्याओं के त्वरित निराकारण हेतु
विभाग द्वारा 24 घण्टे हेल्पलाइन नम्बर – 1912 की व्यवस्था।

सहयोग को सदैव तत्पर

सहकारिता

1. 16.27 लाख रूपे के0सी0सी0 कार्ड का वितरण कर कृषकों को डिजिटल पेमेन्ट सुविधाओं से लाभान्वित किया गया।
2. उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा ग्राहकों को अपने खाते की जानकारी हेतु मोबाईल एप की सुविधा।
3. उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के स्तर से संपादित होने वाली वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु साक्षात्कार समाप्त।
4. वर्ष 2017–18 में 31.40 लाख मी0टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य सापेक्ष अब तक 28.95 लाख मी0टन उर्वरक का वितरण, जो लक्ष्य का 92.19 प्रतिशत है।
5. वर्ष 2017–18 में पी0सी0एफ0 एवं पी0सी0यू0 के माध्यम से 16.00 लाख मै0टन गेंहूँ खरीद के लक्ष्य सापेक्ष कुल 19.25 लाख मै0टन गेंहूँ की खरीद, जो लक्ष्य का 120.32 प्रतिशत है।
6. इससे 466373 कृषक लाभान्वित हुये। गत वर्ष समान अवधि में 3.51 लाख मै0टन गेहूं की खरीद की गयी थी।
7. वर्ष 2017–18 में 17.00 लाख मी0टन धान खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 12.64 लाख मी0टन धान खरीद, जो लक्ष्य के सापेक्ष 74.35 प्रतिशत है।
8. मार्च 2017 में जहां राज्य भण्डारण निगम की कुल क्षमता 35.67 लाख मै0टन थी तथा उपयोगिता 73.17 प्रतिशत थी, जनवरी 2018 में निगम की कुल क्षमता 38.37 लाख मै0टन है तथा उपयोगिता 80.49 प्रतिशत हो गयी है। भण्डारणी सहकारी संस्थाओं को10 प्रतिशत एवं किसानों को 30 प्रतिशत की छूट।
9. माह अप्रैल 2017 से माह फरवरी 2018 तक की अवधि में भण्डारण शुल्क के रूप में रू0 20211.10 लाख प्राप्त हुए हैं, जबकि इसी अवधि में पूर्व वर्ष में रू0 14611.00 लाख प्राप्त हुए, जो विगत वर्ष की तुलना में 138 प्रतिशत अधिक है।

हर दाने की सही कीमत
जरूरतमंद को समुचित खाद्यान्न

खाद्य एवं रसद

37 लाख नये राशन कार्ड बनाये गये जिसमें 1 लाख अन्त्योदय कार्ड शामिल है।

- कृषकों से सीधे 36.99 लाख मी.टन गेहूँ की खरीद पूर्ण, जो गत वर्ष की खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक है।
- गेहूँ की उतराई, छनाई व सफाई रु–03 प्रति कुं0 से बढ़ाकर रु–10 प्रति कुं. का भुगतान, फलस्वरूप कृषकों को रु–36.99 करोड़ समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदान किया गया।
- कृषकों से बिना बिचौलियों के अब तक 42.96 लाख मी.टन धान क्रय कर 6608 करोड़ रुपये का भुगतान।
- धान की सफाई, छनाई व उतराई हेतु रू–03 प्रति कुं. से बढ़ाकर रू–15 प्रति कुं. का भुगतान।
- एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित लगभग 13 हजार उचित दर दुकानों में ई–पॉस मशीनें स्थापित। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यवाही प्रगति पर।
- असहाय, अशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन लाभार्थियों को उचित दर विक्रेता द्वारा उनके निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की पहल

कृषि विकास का बने आधार

किसानों की आय दोगुना करने की पहल

31.03.2016 तक फसली ऋण प्राप्त करने वाले समस्त (86 लाख) लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रूपये की सीमा तक ऋण मोचन। कुल 36 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान। अभी तक तीन चरणों में कुल 34.80 लाख अर्ह किसानों में से 34.11 लाख कृषकों को कुल रू0 20598.31 करोड़ का भुगतान ।

कृषकों की आय दोगुना करने के लिए सी0सी0आई0 एवं मण्डी परिषद, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित Farmers-Agro Industrialist meet "Farmers' First" की संस्तुतियों के अनुसार **किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल)** का आयोजन कर 10 लाख से अधिक कृषकों को कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीक की जानकारी दी गयी।

जैविक प्रमाणीकरण संस्था का राज्य स्तर पर गठन।

प्रथम चरण के 169.69 लाख स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण। द्वितीय चक्र के प्रथम वर्ष के 21.83 लाख नमूने लेकर 15.75 लाख नमूनों का विश्लेषण द्वितीय चरण के भी 45 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण का लक्ष्य।

बुन्देलखण्ड में 3007 तालाबों का निर्माण जिन जनपदों में कृषकों द्वारा तालाब हेतु जमीन उपलब्ध कराने में रूचि नहीं ली जा रही है, उनका अतिरिक्त लक्ष्य बुन्देलखण्ड में आवंटित।

खरीफ 2017 में 25.22 लाख कृषकों की 24.66 लाख हे0 फसलों का रू0 9713.29 करोड़ का बीमा। फसलों की क्षतिपूर्ति प्रारम्भ। रबी 2017–18 में 29.15 लाख कृषकों की 23.58 लाख हेक्टेयर फसलों का रू0 11621.27 करोड़ का बीमा। प्रथम बार 55422 गैर ऋणी कृषकों की फसल का भी बीमा, इससे अवर्षण के कारण बुवाई न होने की दशा में कृषकों को फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा।

सोलर पम्प स्थापना के लक्ष्य के लिए 8120 कृषकों का चयन तथा 1956 पम्पों की स्थापना। इसके अतिरिक्त 10000 अन्य सोलर पम्पों का लक्ष्य भी भारत सरकार से प्राप्त।

बुन्देलखण्ड में 2098 कृषकों को स्प्रिंक्लर सेट वितरण। प्रथम बार स्प्रिंक्लर सेट/ड्रिप पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य।

जैविक खेती के अन्तर्गत हमीरपुर जनपद में 140 क्लस्टर (प्रति क्लस्टर 50 एकड़) में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित। जैविक खेती कार्यक्रम में कुल 1230 क्लस्टर चयन कर 61500 एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती से 61500 कृषक लाभान्वित। 'नमामि गंगे' योजना में 320 क्लस्टरों हेतु रू0 6.80 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त। झांसी व बांदा में आर्गेनिक आउटलेट की स्थापना।

खरीफ 2017 में 7.97 लाख कु0 प्रमाणित बीज वितरण। 2.67 लाख कु0 संकर बीज का वितरण। रबी 2017–18 में अब तक 30.58 लाख कु0 बीज का वितरण। अनुदान की धनराशि रू0 90.77 करोड़ डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के खातों में स्थानान्तरित।

मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु 51165 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का चयन कर रू0 9.41 करोड़ व्यय।

समस्त योजनाओं में 16.78 लाख किसानों के खातों में रू0 249.21 करोड़ की धनराशि सीधे स्थानान्तरित करायी जा चुकी है।

विभिन्न जनपदों में 100 कृषि कल्याण केन्द्र निर्मित कराये जा रहे हैं।

खरीफ में सोयाबीन के मिनी किट 7500 (600 कुन्टल), तिल के मिनीकिट 28799 (288 कुन्टल) निःशुल्क वितरित, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 8799 मिनी किट वितरित। रबी में तोरिया के 70269 मिनी किट एवं राई/सरसों के 183280 (3665 कुन्टल) एवं अलसी के 2700 मिनी किट निःशुल्क वितरित। बुन्देलखण्ड में मुख्य रूप से तिल की खेती को बढ़ावा देने हेतु तिल बीज पर 90 प्रतिशत का अनुदान ।

43 ए0ए0एस0 (एटॉमिक एब्जापर्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर) की आपूर्ति कराकर मृदा में माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स की टेस्टिंग करायी जा रही है।

26.96 लाख मै0 टन उर्वरक का वितरण ।

14575 मै0टन/किली0 कृषि रक्षा रसायन का वितरण।

देश का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र (फिलीपीन्स की शाखा) वाराणसी में स्थापित कराने की कार्यवाही प्रगति पर।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई, बहराइच, गाजीपुर, गोण्डा, जौनपुर, बदायूं हापुड़, लखीमपुर–खीरी, सुल्तानपुर तथा शामली में भूमि की व्यवस्था। मुरादाबाद, रायबरेली, तथा आजमगढ़, एवं श्रावस्ती में चिह्नित भूमि हेतु कार्यवाही गतिमान। है। मुजफ्फरनगर हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान तथा इलाहाबाद में भूमि की व्यवस्था प्रगति पर।

किसानों का मीठा साल

गन्ना विकास

पेराई सत्र 2017–18 में रु. 16,381 करोड़ का भुगतान, जो पेराई सत्र 2016–17 में किये गये भुगतान से रु. 1,466 करोड़ अधिक है। इसके अतिरिक्त पेराई सत्र 2016–17 का रु. 10,044.11 करोड़, पेराई सत्र 2015–16 का रु. 234.88 करोड़ एवं पेराई सत्र 2014–15 का रु. 21.83 करोड़ के बकाये राशि भुगतान कराया गया। इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा अब तक वर्तमान देय एवं बकाया मिलाकर कुल रु. 26,769 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है।

- गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी करते हुए अगेती प्रजाति हेतु रु. 325, सामान्य प्रजाति हेतु रु. 315 प्रति कु. एवं अस्वीकृत प्रजाति हेतु रु. 310 प्रति कु. गन्ना मूल्य का निर्धारण। परिवहन कटौती की दर रु. 8.75 प्रति कु. को घटाकर अधिकतम रु. 8.35 निर्धारित किया गया।
- "पिपराइच–गोरखपुर" एवं "मुण्डेरवा–बस्ती" में 5,000 टी.सी.डी. की क्षमता की नई चीनी मिल स्थापित कराई जा रही है।
- "मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल जिला–मेरठ" की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. कराई गई।
- 'रमाला चीनी मिल जिला–बागपत' का विस्तारीकरण करते हुए इसकी क्षमता 2,750 टी.सी.डी से बढ़ाकर 5,000 टी.सी.डी. की जा रही है तथा 27 मेगावाट का कोजेन संयंत्र लगाया जा रहा है।
- अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत गड्ढामुक्त 1,756 कि.मी. सड़कों की गड्ढामुक्ति/ सुदृढ़ीकरण/ पुनर्निमाण एवं नवनिर्माण कार्य प्रगति पर।
- वर्तमान सत्र में प्रदेश की चीनी मिलों को 15 दिन से 25 दिन पहले संचालित कराया गया।
- गत वर्ष में संचालित कुल 116 चीनी मिलों के अतिरिक्त बन्द निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलें वीनस चीनी मिल–संभल, गागलहेड़ी चीनी मिल–सहारनपुर एवं बुलन्दशहर को पुनः संचालित कराया गया।
- निर्गत सट्टा नीति के अन्तर्गत कृषकों का सट्टा कु.हे. एवं उपज बढ़ोत्तरी की दिशा में 1,300 कु./हे. निर्धारित किया गया जो गत वर्ष क्रमशः 750 एवं 1200 कु./हे. था।

- 60 कु. तक बेसिक कोटा वाले छोटे किसानों की गन्ना आपूर्ति हेतु 45–45 दिन के अंदर उनकी समस्त पर्चियां जारी।
- गन्ना क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित कराते हुए गन्ने की घटतौली पर प्रभावी रोक।
- गन्ने की अवैधानिक खरीद पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 24 मामलों में प्राथमिकी दर्ज, तथा 4559 कुन्टल गन्ना जब्त।
- वैज्ञानिक तकनीकों को गन्ना कृषकों तक पहुँचाने हेतु **एम–किसान पोर्टल** एवं किसान कॉल सेंटर से उन्हें जोड़ा जा रहा है।
- गन्ना किसानों की शिकायतों के निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर 1800–121–3203 की व्यवस्था।
- प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को **"गन्ना किसान दिवस"** का आयोजन।

अन्नदाताओं को पूरा साथ

मण्डी परिषद (कृषि विपणन)

- कृषकों को उपज मण्डी में ले जाने के लिए कुल 7201 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों को से गड्ढामुक्त किया गया।
- गेंहू छनाई–उतराई मद में कृषकों को पूर्व से दिये जा रहे, **रू0 3 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 10 प्रति कुन्तल की सहायता।** धान खरीद योजना में इस सहायता राशि को गत वर्ष के 3 रू0 प्रति कुन्तल से 5 गुना बढ़ाते हुए 15 रू0 प्रति कुन्तल की दर से दिया।
- आलू उत्पादकों के लिए परिवहन भाड़ा अनुदान को **दोगुना** करते हुए, 50 रू0 प्रति कुन्तल की दर से दिया गया।

उत्पादन में हैं नंबर वन

दुग्ध विकास

- दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 5886 में 16 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 6835 किया गया।
- समितियों में सदस्य संख्या में **10 प्रतिशत की वृद्धि** अर्जित करते हुए 3.06 की गई।
- दुग्ध उपार्जन औसत 2.21 लाख किग्रा0 प्रतिदिन से बढ़कर 5.36 लाख किग्रा0 प्रतिदिन तक पहुँच गया है।
- प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले दुग्ध उत्पादक को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि।

- दुग्ध सहकारिता से आच्छादित समिति ग्रामों में दुग्ध की गुणवत्ता लम्बे समय तक बनाये रखने हेतु बल्क मिल्क कूलर की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
- दुग्ध परिवहन में ट्राँजिट हानि को नियंत्रित करने के दृष्टिगत व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) की स्थापना कार्य गतिमान है।
- दुग्ध संघो की संख्या में अभिवृद्धि कर एक नवीन दुग्ध संघ का गठन मथुरा में किया गया है।
- उच्च कोटि के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के नवीन प्लान्ट की स्थापना।
- उच्च कोटि के दुग्ध व दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए 10 नवीन प्लाण्टस् की स्थापना एवं 04 प्लाण्टस् के नवीनीकरण कार्य को गति।
- देशी नस्ल की गायों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने का निर्णय।

पशुपालन

- पशुओं में रोगों के नियंत्रण हेतु निःशुल्क रोग निरोधक टीकाकरण।
- खुरपका–मुँह पका, गलाघोंटू एवं अन्य टीकाकरण अंतर्गत 1198.77 लाख टीकाकरण।
- कृत्रिम गर्भाधान को 132.00 लाख के सापेक्ष 95.22 लाख की पूर्ति।
- स्वदेशी गोवंशीय प्रजातियों के विकास हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।
- 169 भ्रूण स्थानान्तरित किये गये हैं। जिससे उच्च अनुवांशिक गुणवत्तायुक्त साहीवाल नस्ल के नर व मादा संततियां प्राप्त हुई।
- जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा कार्यक्रम अंतर्गत 148000 पशुओं को आच्छादित किया गया है। समस्त मण्डल स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर पर पशु आरोग्य मेले आयोजित।
- तीस हजार कुक्कुट पक्षी क्षमता की 186 इकाईयों तथा दस हजार पक्षी क्षमता की 137 इकाईयों की स्थापना।
- स्थापित कुक्कुट इकाईयों से 61 लाख अण्डों का अतिरिक्त उत्पादन। 22820 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
- राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर गोवंशीय प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाना, गंगातीरी एवं थारपारकर का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा विकास का कार्य।

मत्स्य विकास

मछुआ आवास निर्माण

- गरीब आवासहीन मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान हेतु। 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों का निर्माण। 626 मछुआ आवास निर्माणाधीन।
- मत्स्य पालन हेतु जलापूति के लिए राजकीय मत्स्य राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों में 16 सोलर पंप स्थापित।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

- मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा सुविधा।
- योजनान्तर्गत 1,93,000 मत्स्य पालकों को लाभ।

आंशिक अपंगता– रू0 1.0 लाख

- वर्ष 2017–18 में 07 परिवारों को 02–02 लाख तथा तीन परिवारों को 01–01 लाख रू0 की बीमा धनराशि प्रदान की गयी।

ब्ल्यू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट फार फिशरीज सेक्टर योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्य

- 19.661 हे0 नये तालाबों का निर्माण कराया गया।
- 293.09 हे0 तालाबों का सुधार कराया गया।
- 15.60 हे0 पर मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना कराई गई।
- 06 आटोरिक्शॉ बिद आइस बाक्स उपलब्ध कराए गए।
- 82 बाइसिकल विद आइस बाक्स उपलब्ध कराए गए।
- 56 मोटर साइकिल विद आइस बाक्स उपलब्ध कराए गए।
- 08 मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना कराई गई।
- 01 लघु फीड मिल स्थापित कराई गयी।
- 01 वृहद फीड मिल स्थापित करायी गयी।
- 01 सोलर पावर एक्वाकल्चर स्थापित कराया गया।

लक्ष्य हर खेत को पानी का

सिंचाई एवं जल संसाधन

- पी0एम0के0एस0वाई0 के अन्तर्गत बन्द पड़ी चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ

परियोजना का नाम	आच्छादित जनपद (सं.)	कुल सिंचित क्षेत्रफल (हे.)
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना	09	10.82 लाख
बाण सागर नहर परियोजना	02	1.00 लाख
मध्य गंगा नहर परियोजना	03	0.41 लाख
अर्जुन सहायक परियोजना	03	0.222 लाख

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 1410 करोड़ का बजट प्राविधान। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू 4210 करोड़ काम प्रस्तावित।
- वर्षों से लम्बित बाण सागर नहर परियोजना पूर्ण।
- कनहर सिंचाई परियोजना हेतु रू0 500.00 करोड़ का प्राविधान।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 6 परियोजनाएं पूर्ण।

पहुंज बांध	पथरई बांध
पहाड़ी बांध	लहचुरा बांध
गुण्टा बांध	मौदहा बांध

- बुन्देलखण्ड की अन्य 13 अदद परियोजनाएं दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
- क्षतिग्रस्त 23 अदद तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर।
- जनपद गोरखपुर मे राप्ती नदी के बांये तट पर स्थित मलौनी बांध पर तरकुलानी रेगुलेटर के समीप बाढ़ के पानी की निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

बाग़वानी से सबसे तेज आय में वृद्धि

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 1500 किसानों को तकनीकी जानकारी।
- "प्रथम आवक प्रथम पावक" के आधार पर लाभार्थियों के चयन एवं अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अन्तरण।
- शीतगृहों में भण्डारित आलू का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना लागू। निर्धारित दर रू. 487 प्रति कुन्तल की दर से कृषकों से 1293.80 मीट्रिक टन आलू का क्रय। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से आलू के थोक बाजार भाव में वृद्धि।
- 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना हेतु पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम् रू. 140 लाख के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का निर्णय।
- ऑफ सीजन हाई वैल्यू सब्जी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस का निर्माण। अब तक 2,90,700 वर्ग मीटर में स्थापना का कार्य पूर्ण।

खाद्य प्रसंस्करण विकास

- राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ मे सीटों की संख्या 30 से बढ़ा कर 40 की गयी।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 प्रख्यापित।

सबको हुनर, सबको रोजगार

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- 26 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील। 12,000 नयी प्रशिक्षण सीटें सृजित।
- रोजगार मेलों के माध्यम से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित 13,000 से अधिक प्रशिक्षाणार्थियों को सेवायोजित कराया गया।
- 39 तहसीलों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित। इस प्रकार प्रदेश की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित।
- मात्र एक वर्ष की अवधि में लगभग 3.36 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण एवं 1.15 युवाओं की ट्रेनिंग प्रगति पर।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अन्तर्गत 52 विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत, जिनके द्वारा 67,000 से अधिक गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। अब तक 32,094 युवा इस योजना के अन्तर्गत सेवायोजित।
- स्किल मित्र मोबाइल एप विकसित।
- प्रत्येक जनपद व मण्डल स्तर पर वृहद् रोजगार मेलों के आयोजन का निर्णय। इस श्रृखंला में गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूं, बरेली एवं वाराणसी मण्डलों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से कुल 20000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की रूचि विकसित करने के लिए हब एण्ड स्पोक मॉडल पर आधारित स्किल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया गया है। इसके द्वारा किसी प्रशिक्षण केन्द्र के 15 किलोमीटर की सीमा में आने वाले समस्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्र से जोड़ा गया है ताकि युवाओं को विद्यालयों में ही कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके।

तकनीक से मिला मजबूत आधार

प्राविधिक शिक्षा

- 19 राजकीय पालीटेक्निकों एवं 17 छात्रावासों का निर्माण पूर्ण।
- 33 पालीटेक्निकों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा ।
- अलीगढ़, आगरा एवं बस्ती मण्डलों में एक–एक राजकीय महिला पालीटेक्निक तथा जनपद इलाहाबाद में दो तथा सहजनवां गोरखपुर में एक नये राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।
- 15 राजकीय पालीटेक्निकों में महिला छात्रावास निर्मित कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

प्रतापगढ़ में नये इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लेते हुए निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा व राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर के निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत।

- **डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन हेतु प्रमुख जनपदों में स्थित 10 राजकीय पालीटेक्निकों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना । संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ में सेन्ट्रल प्लेसमेंट सेल की स्थापना।**

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को अपने नवीन भवन में संचालित कराते हुए उक्त भवन में सेन्टर फार एडवांस स्टडीज का संचालन।

- डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के नोएडा कैंपस में इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन का संचालन।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना के अंतर्गत सभी शासकीय अनुदानित संस्थाओं को रू0 200.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
- नवस्थापित इंजीनियरिंग कालेजों सोनभद्र, मैनपुरी तथा कन्नौज का संचालन उनके नवीन परिसरों में प्रारम्भ।

उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्मित होने वाले 02 राजकीय महिला पालीटेक्निक, 01 राजकीय पालीटेक्निक एवं 15 महिला छात्रावासों का शिलान्यास ।

छोटे उद्योगों में बड़ा रोज़गार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

- पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए **''एक जनपद–एक उत्पाद''** योजना प्रारम्भ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017 निर्गत। पूँजी निवेश हेतु 695 एमओयू हस्ताक्षरित, जिनमें रू. 23324.59 करोड़ का निवेश एवं 1,61,000 रोजगार सृजन संभावित।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य रू0 111.57 करोड़ एवं भौतिक लक्ष्य 5625 लाभार्थी के सापेक्ष 87 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त।
- शासकीय विभागों में सामग्री व सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेथस (Gem) अंगीकृत।
- उद्यमियों को आनलाइन एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत niveshmitra.up.nic.in पोर्टल लागू।
- सी0एफ0सी0 पैकेजिंग एण्ड स्टोरेज फार फूड एण्ड वेजटेबिल, लखनऊ की परियोजना का लोकार्पण।
- डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरी इण्डस्ट्रीज, लखनऊ की परियोजना का लोकार्पण। परियोजना से अब तक 1223 कारीगर जुड़े।
- सी0एफ0सी फॉर डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, मुरादाबाद का लोकार्पण।
- मुरादाबाद में सीएफसी फॉर मेटल कम्पोनेंट एण्ड मेटल प्रोसेसिंग सेंटर की परियोजना का लोकार्पण।
- रू0 2448.20 लाख की दो परियोजनाओं– मोनो फिलमेंट यार्न क्लस्टर, कानपुर एवं कार्पेट एवं दरी क्लस्टर, सोनभद्र को सैद्धांतिक स्वीकृति।

एक जनपद एक उत्पाद
उत्तर प्रदेश

स्थानीय उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग

क्र.सं.	जनपद	चिन्हित उत्पाद
1.	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक)
2.	अमेठी	मूँज उत्पाद
3.	अलीगढ़	ताले एवं हार्डवेयर
4.	अम्बेडकर नगर	वस्त्र उत्पाद
5.	आगरा	चमड़े के उत्पाद
6.	आज़मगढ़	काली मिट्टी की कलाकृतियाँ

क्र.सं.	जनपद	चिन्हित उत्पाद
7.	इटावा	वस्त्र
8.	इलाहाबाद	मूँज उत्पाद
9.	उन्नाव	ज़री-ज़रदोज़ी
10.	एटा	घुंघरू, घंटी
11.	औरैया	दूध प्रसंस्करण (देशी घी)
12.	कन्नौज	इत्र

क्र.सं.	जनपद	चिन्हित उत्पाद
13.	कानपुर देहात	जस्ते के बर्तन
14.	कानपुर नगर	चमड़े के उत्पाद
15.	कासगंज	ज़री-ज़रदोज़ी
16.	कुशीनगर	केले के रेशे से बने उत्पाद
17.	कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण (केला)
18.	गाज़ियाबाद	यांत्रिकी उत्पाद
19.	गाजीपुर	जूट वॉल हैंगिंग्स
20.	गोरखपुर	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा)
21.	गोण्डा	खाद्य प्रसंस्करण (दाल)
22.	गौतमबुद्धनगर	सिले-सिलाए वस्त्र
23.	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने
24.	चन्दौली	ज़री-ज़रदोज़ी
25.	जालौन	हस्त निर्मित कागज
26.	जौनपुर	ऊनी दरी
27.	झांसी	कोमल खिलौने (सॉफ्ट ट्वॉयज)
28.	देवरिया	सजावटी उत्पाद
29.	पीलीभीत	बांसुरी
30.	प्रतापगढ़	खाद्य प्रसंस्करण (आँवला)
31.	फतेहपुर	बेडशीट
32.	फ़र्रूख़ाबाद	ब्लॉक प्रिंटिंग
33.	फिरोज़ाबाद	कांच उत्पाद
34.	फ़ैज़ाबाद	गुड़
35.	बदायूँ	ज़री-ज़रदोज़ी
36.	बरेली	ज़री-ज़रदोज़ी
37.	बलरामपुर	खाद्य प्रसंस्करण (दाल)
38.	बलिया	बिन्दी
39.	बस्ती	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
40.	बहराइच	गेहूँ के डंठल की कलाकृतियाँ
41.	बागपत	घरेलू सजावटी सामान
42.	बाराबंकी	हथकरघा उत्पाद
43.	बांदा	शज़र पत्थर शिल्प
44.	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
45.	बुलन्दशहर	चीनी मिट्टी के बर्तन (पॉटरी)

क्र.सं.	जनपद	चिन्हित उत्पाद
46.	मऊ	वस्त्र उत्पाद
47.	मथुरा	स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण
48.	महराजगंज	फर्नीचर
49.	महोबा	गौरा पत्थर शिल्प
50.	मिर्ज़ापुर	कालीन
51.	मुज़फ्फरनगर	गुड़
52.	मुरादाबाद	धातु शिल्प
53.	मेरठ	खेल का सामान
54.	मैनपुरी	तारकशी कला
55.	रामपुर	पैचवर्क
56.	रायबरेली	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
57.	लखनऊ	चिकनकरी एवं ज़री ज़रदोजी
58.	लखीमपुर खीरी	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)
59.	ललितपुर	ज़री सिल्क साड़ी
60.	वाराणसी	रेशम उत्पाद
61.	शामली	रिम एवं धुरा (एक्सेल)
62.	शाहजहाँपुर	ज़री-ज़रदोज़ी
63.	श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)
64.	सम्भल	सींग एवं अस्थि उत्पाद
65.	सहारनपुर	काष्ठ शिल्प (वुड कार्विंग)
66.	सिद्धार्थनगर	खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक चावल)
67.	सीतापुर	दरी
68	सुल्तानपुर	मूँज उत्पाद
69.	सोनभद्र	कालीन
70.	संत कबीर नगर	पीतल के बर्तन
71.	संत रविदास नगर (भदोही)	कालीन
72.	हमीरपुर	जूती
73.	हरदोई	हथकरघा
74.	हाथरस	हींग प्रसंस्करण
75.	हापुड़	घरेलू सजावटी सामान

बदल रहा परिवेश, बढ़ रहा निवेश

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू।
- मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंतर्गत एक समर्पित 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग' की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने हेतु प्रदेश में एक समर्पित ''मेक इन यूपी'' विभाग की स्थापना।
- निजी क्षेत्र को बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल तथा मध्यांचल में विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों तथा एग्रो पार्कों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र में स्थापित इकाईयों की सुरक्षा हेतु समर्पित पुलिस बल की तैनाती।
- लखनऊ में दिनांक 21 व 22 फरवरी, 2018 को 'यूपी इन्वेस्टर समिट–2018' का सफल आयोजन। देश–विदेश के उद्योगपतियों द्वारा रू0 4.68 लाख करोड़ निवेश के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।
- **ईज आफ डुइंग बिजनेस**
- ईज आफ डुइंग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (BRAP-2017) लागू।
- निवेश मित्र सिंगल विण्डो वेब पोर्टल का लोकार्पण।
- सिंगल विण्डो वेब पोर्टल से सभी सम्बन्धित विभागों का ऑन–लाइन इन्टीग्रेशन।
- मेसर्स सैमसंग की रू0–4915.00 करोड़ की परियोजना एवं मेसर्स इन्टेक्स की रू0–372.00 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। इससे लगभग 8254 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा सहित सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का आडिट कराने का निर्णय।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, निगमों तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ई–प्रोक्योरमेन्ट/ ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया लागू। सभी अधीनस्थ संस्थाओं में सेवाओं/वस्तुओं के क्रय के लिए गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लस (GeM) को लागू।
- उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर–33 में द्वितीय इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का नियोजन।

- जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी नामित।
- देश के **सबसे बड़े एक्सप्रेस–वे** के निर्माण के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय। अब तक लगभग 85.09 प्रतिशत भूमि क्रय/अधिग्रहीत। लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किमी0 लं. में रू0 23598.118 करोड़ की लागत से निर्मित होगा।
- गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का महत्वपूर्ण निर्णय।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोड़ने हेतु बुन्देलखण्ड लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय।

दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन

- 'दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र' (डी.एन.जी.आई.आर.) में सम्मिलित 80 ग्राम विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित।
- ग्रेटर नोएडा में इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट एवं एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नौएडा की भूमि एस0पी0वी0 को हस्तान्तरित।
- ट्रन्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन कार्य के अंतर्गत तलपट मानचित्र, डिजाईन बेसिस रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, ई.आई.ए. डॉक्यूमेंट तैयार।
- दादरी में मल्टी माडल लॉजिस्टिक हब परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थल का अनुमोदन एवं प्राधिकरण द्वारा 319.88 एकड़ भूमि का अधिग्रहण/क्रय।

अमृतसर–दिल्ली कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना

- · परियोजना के अन्तर्गत 03 क्षेत्रों भाऊपुर (कानपुर के समीप), अलीगढ़ एवं इलाहाबाद का चयन।
- · मेसर्स ली एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रदेश में प्रथम इन्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु कानपुर के समीप भाऊपुर में 2500 एकड़ भूमि की अधिसूचना जारी।

सँवरेगी नगरों की किस्मत

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

शहरी क्षेत्र के 3.25 लाख से अधिक आवासविहीन लोगों के आवास स्वीकृत हैं, जिसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नवीन) हेतु 2,81,256, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) के 19,697 तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 24,266 आवास स्वीकृत।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन

- ❖ महिला सशक्तीकरण हेतु लगभग 70000 महिलाओं को संगठित कर सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण हेतु 6905 समूहों का गठन कर 3822 समूहों को रु0 10,000/– प्रति समूह रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त।
- ❖ शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत शहरी निराश्रितों के लिए 48 शेल्टर होम का संचालन। इसके अतिरिक्त 74 शेल्टर होम निर्माण की प्रक्रिया में हैं।
- ❖ प्रदेश के शहरी पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किये जाने हेतु पथ विक्रेताओं के चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तुरन्त बाद उनको पुनर्स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

स्मार्ट सिटी का सपना होगा पूरा

देश के 99 में से सर्वाधिक 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में

नगर विकास

स्मार्ट सिटी मिशन

❖ **लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली, आगरा स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के लिए चयनित।**

स्वच्छ भारत मिशन

❖ मिशन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में 11.05 लाख लोगों को खुले में शौच से मुक्त करने का मिशन।

❖ अद्यतन 4,32,201 शौचालयों का निर्माण।

❖ सामुदायिक शौचालय के लिए 11 हजार सीटों का निर्माण।

❖ जन शौचालय के निर्माण के लिए 13,598 सीटों का निर्माण।

❖ 6,356 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रगति पर।

❖ वेस्ट टू कम्पोस्ट के वर्तमान में कुल 11 प्लान्ट क्रियाशील। 06 अन्य अक्रियाशील हैं, जिनमें से 5 में पुनः टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है, एक अन्य में कार्य प्रगति पर।

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत)

❖ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक प्रदेश के 60 शहरो में जलापूर्ति, हरित क्षेत्र व खुले मैदान हेतु कार्य प्रगति पर।

❖ योजना में अब तक 130 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 1,20,000 नग निजी पेयजल संयोजन किए गए हैं, जिससे 6 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं एवं 93,000 नग मिनी सिवरेज़ कनेक्शन प्रदान कर 5,65,000 लोग लाभान्वित किए गए हैं।

नमामि गंगे

❖ गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों के किनारे स्थित शहरों हेतु स्वीकृत 19 परियोजनाओं में से 04 परियोजनाएं पूर्ण। अन्य 09 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर, जिसमें से 06 परियोजनाएं मार्च तक पूर्ण हो रही हैं।

❖ सभी नगर निगम में एल.ई.डी. लाईट लग रू0 1,692.17 करोड़ की नई परियोजनाएं स्वीकृति।

❖ गंगा नदी के किनारे स्थित उ0प्र0 के 25 जनपदों में जिला गंगा समितियों का गठन।

एल.ई.डी लाइट

❖ सभी नगर निगम में अब तक 3.50 लाख एल. ई. डी. लाईट्स लगाने का काम शुरू, अप्रैल तक कार्य पूरा होगा।

राज्य सेक्टर

❖ राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 10 पेयजल, 2 सीवरेज़ एवं 2 ड्रेनेज़ की कुल 14 योजनाएं पूर्ण कर जन सामान्य को लाभान्वित किया।

सुनियोजित विकास, सबको आवास

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के माध्यम से प्रथम चरणः कुल 18598 निर्मित किये जाने वाले दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त चुकी है। निर्माण शीघ्र प्रारम्भ होगा। द्वितीय चरणः विकास प्राधिकरणों द्वारा कुल 5668 निर्मित किये जाने वाले दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय समिति को भेजा जा चुका है।

(ब) निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड् :–

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। जनपदों में निजी विकासकर्ताओं द्वारा कुल 8099 भवनों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(स)इस प्रकार कुल 24,266 आवासों पर काम प्रारम्भ हो चुका है।

- यूपीरेरा (UPRERA) के गठन की कार्यवाहीचल रही है।
- वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अथॉरिटी के गठन तक रीयल इस्टेट अथॉरिटी घोषित किया जा चुका है।

- समस्त अभिकरणों द्वारा स्वीकृत ले–आउट अभिकरणों की योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों का मानचित्र आन–लाइन पद्धति से स्वीकृति करने हेतु साफ्टवेयर विकसित कराया गया है। उपर्युक्तानुसार समस्त अभिकरणों में ऑनलाइन–मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था लागू कर दी गयी है, प्रदेश में 3982 मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत किए जा चुके है।

- चालू वित्तीय वर्ष में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा 117.47 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से रिक्त करायी गयी है।

- लखनऊ मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन (ट्रॉसपोर्ट नगर से चारबाग) का व्यवसायिक संचालन दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को प्रारम्भ किया जा चुका है। गाजियाबाद मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। कानपुर, आगरा एवं मेरठ में नई मेट्रो नीति के तहत डी0पी0आर0 तैयार कर मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। गोरखपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद में मेट्रो रेल सेवा आरम्भ किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी नई मेट्रो रेल नीति–2017 के अनुसार डी0पी0आर0 तैयारी प्रगति पर है।

सुगम यातायात

परिवहन

- प्रदेश के **7583 असेवित गाँवों को** बस सेवा से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **''संकल्प सेवा''** नाम से 50 नयी बसों का एक्सक्लूसिव संचालन।
- राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हरियाणा के साथ **पारस्परिक परिवहन करार** हस्ताक्षरित।
- परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9688 किमी के 379 **मार्गों का रूट फार्मूलेशन** किया गया।
- वाहन चालान की कार्यवाही को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से **ई–चालान व्यवस्था** लागू। **यह व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।**
- 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत One Nation & One RTO की संकल्पना पर एनआईसी द्वारा तैयार **'वेबसाइड** VAHAN **4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम** (https://parivahan-gov-in/vahanservice) प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में लागू।
- एनआईसी द्वारा विकसित **सारथी 4.0 एप्लीकेशन सिस्टम** (https://parivahan-gov-in/sarathiservice) का क्रियान्वयन 20 परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ। आगामी 8 सप्ताह में प्रदेश के सभी कार्यालयों में इसका क्रियान्वयन पूर्ण किये जाने की योजना।
- कानपुर एवं बरेली में **आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक** का निर्माण कराया गया है।
- माह के प्रत्येक बुधवार को **हेल्मेट व सीटबेल्ट दिवस** घोषित।

- **कुम्भ 2019** में श्रद्धालुओं को सुविधा हेतु बस स्टेशन जीरो रोड, बस स्टेशन झाँसी, बस स्टेशन सिविल लाइन, जारी बाजार बस स्टेशन के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **विन्ध्याचल में बस स्टेशन का निर्माण एवं बरसाना (मथुरा) बस स्टेशन का जीर्णोद्धार** कार्य प्रारम्भ।
- गोरखपुर में कचहरी बस स्टेशन एवं नौसड़ बस स्टेशन, अमरोहा में हसनपुर, मेरठ में भैंसाली एवं गाजियाबाद में मोदीनगर बस स्टेशन का शिलान्यास।
- गोरखपुर, मुबारकपुर, बिजनौर, बेवर (मैनपुरी), भोगाँव (मैनपुरी), करहल (मैनपुरी), महोबा, शाहजहाँपुर एवं महमूदाबाद (सीतापुर) में **बस स्टेशनों का लोकार्पण।**
- **18 प्रमुख बस स्टेशनों को पी.पी.पी. पद्धति** पर बनाने की कार्यवाही शुरू
- **परिवहन डिपो कार्यशाला गोरखपुर एवं क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर** का शिलान्यास।
- **12 वॉल्वो/स्कैनिया एवं 16 जनरथ बसों** का संचालन कर नयी वातानुकूलित बस सेवा की शुरूआत।
- परिवहन निगम द्वारा 650 साधारण बसों, 250 सीएनजी बसों एवं 100 एसी बसों के क्रय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- **रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश में पहली बार महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा।**
- 10 बस स्टेशनों– वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा एवं इटावा में **वाटर ए0टी0एम0** स्थापित।
- **4700 साधारण बसों के लिये आनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा।**
- टोल के इलेक्ट्रानिक भुगतान हेतु परिवहन निगम की समस्त बसों में **रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेन्टिफिकेशन डिवाइस (आर.एफ. आई.डी) फास्ट टैग** लगाया गया है।
- निगम के **73 डिपो में ऑटोमेटेड फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम** लागू।
- **निर्भया फण्ड – उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए चयनित किया गया है।** निर्भया फण्ड के माध्यम से निगम की सभी 12500 बसों में पैनिक बटन एवं सी0सी0टी0वी कैमरे लगेंगे, जिससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक

पंचायती राज

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस समय तक 15,02,326 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में 37,26,947 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में ढ़ाई गुना से अधिक है।
- प्रदेश के कुल 98,498 ग्रामों में से 19,591 ग्राम खुले में शौच मुक्त(ओ.डी.एफ.) घोषित, वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस समय तक 4,779 ग्रामों को खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित हुए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में 13,561 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया जा चुका है, जो जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विवरण	सरकार गठन के समय की स्थिति	सरकार के गठन से अब तक की अवधि में अद्यतन प्रगति	निर्धारित अवधि में प्रगति
1	बेसलाइन के सापेक्ष शौचालय आच्छादन की स्थिति			
	शौचालय आच्छादन का प्रतिशत	47%	60%	13%
	शौचालय विहीन परिवारों की संख्या	151 लाख	110 लाख	41 लाख
2	**खुले में शौच मुक्त ग्राम/ग्राम पंचायत/विकास खण्ड**			
	खुले में शौच मुक्त ग्रामों की संख्या	6030	19591	13561
	खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या	2611	8403	5792
	खुले में शौच मुक्त विकास खण्डों की संख्या	06	48	42
	खुले में शौच मुक्त जनपदों की संख्या	01 (शामली)	08 (शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर)	07

कनेक्टिविटी से निवेश को उड़ान

नागरिक उड्डयन

जेवर (गौतम बुद्ध नगर) में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट : जेवर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापना के लिए भारत सरकार से साईट क्लियर हो चुकी है। गृह विभाग की अनापत्ति प्राप्त हुई है। भारत सरकार से इन–प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए टेक्नो इकनोमिक फिजिबिलिटी स्टडी PWC से कराई जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण हेतु 1206 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की प्रक्रिया गतिशील।

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम : प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने तथा विभिन्न जनपदों को हवाई सेवा से जोड़े जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 प्रख्यापित। रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम में उत्तर प्रदेश के 9 एअरपोर्ट व 22 एयर रूट चयनित हुए हैं, विशेषतया इलाहाबाद से 13 नगरों के लिए विमान सेवा प्रारम्भ होंगी। इस प्रकार 11 मंडल मुख्यालयों/जिलों से नई उड़ान सेवा शीघ्र ही प्रारम्भ हो सकेगी।

एयरपोर्ट्स का विकास

लखनऊ एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु 69 एकड़ भूमि क्रय कार्य प्रगति पर।

गोरखपुर में 100 यात्रियों के आवागमन हेतु महायोगी गोरक्षनाथ सिविल टर्मिनल का मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन। दिल्ली–कोलकाता से एयर कनेक्टिविटी मिली।

शहीद पथ से एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग PWD के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने हेतु नाला निर्माण/सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।

आगरा, इलाहाबाद, बरेली तथा कानपुर एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु भूमि के लिए आवश्यक धनराशि अवमुक्त।

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा **कानपुर देहात** में नई हवाई पट्टी के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त।

मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, सोनभद्र (म्योरपुर), कुशीनगर, श्रावस्ती तथा चित्रकूट हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट्स के रूप में अपग्रेड करने का कार्य प्रगति पर।

गांव गांव में हो विकास

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना** के कुल आवास 8.85 लाख के सापेक्ष 6.20 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण। शेष सभी आवास 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।

- वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं लोहिया आवास को मिलाकर कुल 9.10 लाख आवास स्वीकृत।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- वर्ष 2017–18 में अब तक 2697 कि0मी0 सड़कें निर्मित।
- अभियान चलाकर 10217 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त की गयी।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 430 पयजल परियोजनाएं पूर्ण।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

- प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) में स्थित ऐसे गांव जहाँ आजादी के बाद से अभी तक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा वनटांगिया, मुसहर एवं थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में वस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है। ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित करने हेतु **'' मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना''** का शुभारम्भ किया गया है। इसी प्रकार देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक संरचनाओं की दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्रामों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

- मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार बेस्ड पेमेंन्ट सिस्टम को लागू कर ए0बी0पी0एस0 से जुड़े श्रमिकों की संख्या जो वर्ष 2016–17 में 22 लाख थी, बढ़ाकर 66 लाख कर दिया गया है, **जो गत वर्ष की तुलना में तीन गुना** है।
- सृजित परिसम्पतियों की जियो टैगिंग जो वर्ष 2016–17 में 4.13 लाख थी, को वर्ष 2017–18 में बढ़ाकर 37.82 लाख कर दिया गया है, **जो गत वर्ष की अपेक्षा 9 गुना अधिक** है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत नये 43,529 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 14,935 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है, जबकि वर्ष 2016–17 में जनवरी, 2017 तक 35,944 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं 9,464 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी थी।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

fn0;kx tuk
d ifr
lonu'khy ljdkj

उत्तर प्रदेश
राज्य सड़क परिवहन निगम
की साधारण श्रेणी की बसों में
निःशुल्क यात्रा अनुमन्यता
प्रदेश सीमा से बढ़ाकर
अंतिम गंतव्य स्थल तक
बढ़ाई गयी

विकलांगजन
विकास विभाग है अब
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु
हेल्पलाइन नम्बर
1800-180-1995
प्रारम्भ की गयी है

बधिर बच्चों की
कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी
हेतु अनुदान राशि प्रति सर्जरी
6,00,000 रुपये
की गयी।

शल्य चिकित्सा
अनुदान की धनराशि बढ़ाई गई
8000 रूपये से बढ़ाकर
10000 रूपये
की गयी।

भरण-पोषण
अनुदान को 300 रूपये प्रतिमाह से
बढ़ाकर 500 रूपये
प्रतिमाह

शादी-विवाह
प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाई गई
20000 रूपये से 35000 रूपये प्रति दंपति
(युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में)

कृत्रिम अंग एवं
सहायक उपकरण योजनान्तर्गत सहायतार्थ
दी जाने वाली धनराशि की सीमा।
रू0 6000/- से बढ़ाकर रू0 8000/- प्रति दिव्यांग की गयी।
पहली बार
सहायक उपकरणों के साथ कृत्रिम अंग लगाया जाना अनुमन्य।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले
समाज से संगठनों/व्यक्तियों को प्रतिवर्ष
दी जाने वाली पुरस्कार राशि
रू0 5000/- से बढ़ाकर रू0 25000/- की गई

पिछड़ा वर्ग कल्याण

छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल 880096 छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन। राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी के दौरान पात्र पाये गये 317571 छात्र/छात्राओं की धनराशि सीधे उनके खातों में प्रेषित।

कुल रू0 70 हजार लाख का बजट। कुल 13 लाख 65 हजार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रेषित।

लगभग 1114000 छात्र-छात्राओं को धनराशि सीधे उनके खाते में प्रेषित

- ❑ ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत **रू. 154.00 करोड़ के बजट के सापेक्ष 77000 लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में धनराशि भेजने का लक्ष्य।**
- ❑ प्रदेश में ''ओ'' लेवल के अन्तर्गत **कुल 6735 तथा सी.सी.सी. के अन्तर्गत 2565 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण ।**
- ❑ छात्रावास निर्माण योजना के अन्तर्गत **जनपद गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, जालौन, बहराइच, कुशीनगर, रामपुर एवं आजमगढ़ में छात्रावास निर्माणाधीन।**

अल्पसंख्यक कल्याण

- ◎ एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत 45 इण्टर कालेजों 22 नवीन आई0टी0आई0 भवनों एवं 03 पालीटेक्निकों का निर्माण पूर्ण ।
- ◎ एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत 20 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना तथा 436 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर पेयजल सुविधाओं का सृजन।
- ◎ पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 06 आयुष चिकित्सालयों का निर्माण।
- ◎ 348 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूर्ण ।
- ◎ 05 इण्टर कालेज, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, 28 पेयजल परियोजनाओं तथा 23 आंगनवाड़ी केन्द्रों का शिलान्यास ।

> हज के दौरान सऊदी अरब में यात्रियों को सुविधा पहुँचाने हेतु हज–2017 में प्रदेश सरकार की ओर से 145 खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) सऊदी अरब भेजे गये। जबकि विगत पॉच वर्षों से कोई खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) प्रदेश सरकार की ओर से यात्रियों की सेवा हेतु नहीं भेजा गया था।

- ◎ मदरसा पोर्टल लांच।
- ◎ मदरसों में शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने चरणबद्ध रुप में NCERT का पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया है।
- ◎ हज–2017 में हज यात्रियों के कोटे में लगभग सात हजार की वृद्वि करायी गयी। इसी प्रकार हज सत्र–2018 में भी प्रदेश सरकार से लगभग तीस हजार यात्री हज पर जायेंगे।
- ◎ हज–2018 के लिए ऑन–लाइन आवेदन सुविधा।
- ◎ हज–2018 में पहली बार **महिला आवेदकों को बिना महरम आवेदन करने की सुविधा।**

डेढ़ गुना अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति

समाज कल्याण/जनजाति कल्याण

- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 3618384 वृद्धजनों को रू0 16728.22 लाख निर्गत।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के 754734 अनुसूचित जाति के 1059385 छात्र तथा अनुसूचित जनजाति के 21511छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर।
- पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित है, जिनमें लगभग 4000 वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, दवा, मनोरंजन तथा अन्य व्यवस्थायें उपलब्ध करायी जा रही है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा 93 तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा कुल 102 पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, जिनमें से 45 विद्यालयों को CBSE बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करायी जा रही है। कुल 30 आश्रम पद्धति विद्यालयों में हाईटेक शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये गये हैं।
- अनुसूचित/जनजाति के प्रतिभावान छात्रों को आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रदेश में 07 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।
- अनुसूचित/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित परिवारों को भारत सरकार की तदविषयक नियमावली के अन्तर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर न्यूनतम रू 85,000/– से लेकर रू 8,25,000/– तक कर दिया गया है।

विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति–रिवाजों के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना नाम से नवीन योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत अभी तक विभिन्न समुदायों के 6966 जोड़ों (दिव्यांगजन सहित) की शादी प्रदेश के 60 जनपदों में सम्पन्न करायी जा चुकी है।

काम को सम्मान

कार्मिक

- ☆ राज्याधीन सेवाओं में 16000 से अधिक कार्मिकों की पदोन्नति।
- ☆ समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के पदों पर चयन से **साक्षात्कार का प्राविधान समाप्त**।
- ☆ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं 05 सदस्यों के पद पर नियुक्ति।
- ☆ सी–सैट से प्रभावित, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए वर्ष 2017 एवं 2018 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय।
- ☆ गम्भीर आरोपों के दृष्टिगत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01–04–2012 से दिनांक 31–3–2017 तक घोषित परीक्षा परिणामों की जांच। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के गठन से लेकर मार्च, 2017 तक की अवधि में आयोग द्वारा की गयी भर्तियों की जांच।

शहीदों का सम्मान एवं उनके परिजनों को सहायता

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

सेनाओं के तीनों अंगों के शहीद जवानों और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिये जाने का निर्णय।

द्वितीय विश्व युद्ध

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा वीर नारियों को आर्थिक सहायता के रूप में 3397 लाभार्थियों को 25.90 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित की गयी।

प्री–कारगिल युद्ध– की वीर नारियों को आर्थिक सहायता

1962 के युद्ध, 1965 के युद्ध एवं 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों की आठ वीर नारियों को रू0 चार लाख की धनराशि वितरित। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के 100 माता–पिता एवं वीर नारियों को रू0 35.85 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। 564 वीर नारियों को इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, कम्प्यूटर टैली एवं कम्प्यूटर फैशन डिजायनिंग का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 59 लाख की धनराशि व्यय।

वीरता/विशिष्ट पदक विजेताओं को देय अनुदान

वीरता/विशिष्ट पदक विजेताओं के लिये 946 लाभार्थियों को रूपये 10.27 लाख की स्वीकृत धनराशि कुल वितरित।

सशक्त नारी समान अधिकार

महिला एवं बाल विकास

सभी जनपदों में 181 महिला हेल्पलाइन व रेस्क्यू वैन सेवाएं उपलब्ध

- 181 महिला हेल्पलाइन व रेस्क्यू वैन सेवाओं का विस्तार 11 जनपदों से बढ़ाकर सभी 75 जनपदों में किया गया।
- हेल्पलाइन के काल सेन्टर की क्षमता 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर प्रति शिफ्ट की गयी।
- एक लाख तीन हजार टेलीफोन कॉल प्राप्त की गयीं, जिसमें 22 हजार महिलाओं को रेस्क्यू एवं साइट काउन्सिलिंग एवं 78 हजार महिलाओं को टेली काउंसिलिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की गयी।
- प्रथम बार विभिन्न शिक्षा परिषदों की मेरिट में से प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को **रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार** रू0 01.00 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- प्रथम बार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता फैलाने हेतु वृहद स्तर पर महिला बाईकर्स रैली का आयोजन।
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य स्तर पर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सेल का गठन ।
- प्रथम बार अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं उपेक्षित बच्चों में से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले 22 बच्चों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया।
- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी गयी।
- लाभार्थियों की पात्रता की आय सीमा रूपए दो लाख की गयी।
- सभी निराश्रित महिलाओं को पात्र माना गया, चाहे उनके पुत्र बालिग हों या नाबालिग।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 1435 बालिकाओं / महिलाओं को रू0 53.64 करोड़ की क्षतिपूर्ति।

- ❖ प्रदेश में पहली बार लगभग 2000 ग्राम पंचायतों में महिला एवं बाल अधिकार मंच का गठन।
- ❖ 110 नारी अदालतों का गठन, जिनके द्वारा 12480 घरेलू हिंसा के प्रकरणों का निस्तारण।
- ❖ 135 नारी संजीवनी केन्द्रों का गठन।
- ❖ बाल अधिकार मंच के माध्यम से 176 बाल विवाह को ग्राम स्तर पर रोकने का सफल प्रयास।
- ❖ विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साफ्टवेयर तैयार कराने का कार्य स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा किया गया है।

बच्चों को पूरा पोषण

बाल विकास एवं पुष्टाहार

शबरी पोषण मोबाइल एप

कुपोषण के संबंध में जनसामान्य को जागरूक करने के दृष्टिगत शबरी पोषण मोबाइल एप लान्च। फोन पर इसे डाउनलोड कर 2 वर्ष तक के बच्चे का वजन फीड करने पर उसे पोषण संबंधी उचित परामर्श उपलब्ध। गर्भवती महिला के हिमोग्लोबिन को फीड करने पर उसे पोषण संबंधी उचित परामर्श भी इस एप पर उपलब्ध।

कुपोषण मुक्त गाँव

बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिये कुपोषण मुक्त गाँव योजना लागू। प्रत्येक जनपद में जिला स्तर के अधिकारी को दो गाँव गोद लेकर स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों से गाँव को संतृप्त कराकर 6 माह के अन्दर गाँव को कुपोषण मुक्त घोषित करना है। वर्तमान में प्रदेश के 3171 अधिकारियों द्वारा 6216 गाँव गोद लिये जा चुके हैं।

पोषण पखवाड़ा

कुपोषण के प्रति जागरूकता लाने उद्देश्य से प्रत्येक जनपद, ब्लाक एवं आंगनबाड़ी स्तर पर दिनांक 16 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2017 तक पोषण पखवाडे का आयोजन। पखवाड़े में गभर्वती धात्री महिलायें, नवजात शिशु, बच्चे एवं किशोरी बालिकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ विशेषज्ञों, नुक्कड नाटक मंडलियों एवं मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करायी गयीं।

बचपन दिवस, ममता दिवस एवं लाडली दिवस

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 05 तारीख व 15 तारीख एवं 25 तारीख को लाडली दिवस को लाभार्थियों में अनुपूरक पोषाहार (टेक होम राशन) का वितरण किये जाने की व्यवस्था।

समुदाय आधारित गतिविधियां (गोद भराई एवं अन्नप्राशन)

मातृ–शिशु पोषण स्तर में सुधार एवं समुदाय में आई0वाई0सी0एफ0 के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्निप योजना के अन्तर्गत आच्छादित 41 जनपदों के कुल 91,179 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समुदाय आधारित गतिविधियां (गोदभराई एवं अन्नप्राशन) का आयोजन। कुल 970065 गतिविधियां का आयोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संपन्न।

प्रतिभा को सम्मान प्रदेश को नई पहचान

खेल

1. प्रदेश में प्रथम बार पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में प्रत्येक जनपद में 02–02 जिला स्तरीय प्रतियोगितायें कुल–148 एवं प्रत्येक मण्डल में 01–01 राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें कुल–18 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन।

2. प्रदेश में प्रथम बार 24 जनवरी, 2018 को उ0प्र0 दिवस के अवसर पर लखनऊ में हाकी, कुश्ती, कबड्डी खेल के दोनों वर्गों महिला/पुरुष में 06 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया।

3. 79 राज्य स्तरीय, 1063 जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिताओं के आयोजन में 77,67,400 रू व्यय किया गया।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 02 खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय चौम्पियनशिप आयोजित करायी गयी।

5. लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के अन्तर्गत प्रदेश के 14 विशिष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

6. उ0प्र0 दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा रियो ओलम्पिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 खिलाड़ियों सुश्री पी0वी0 सिन्धु (बैडमिण्टन), सुश्री साक्षी मलिक (कुश्ती), सुश्री दीपा करमाकर (जिमनास्टिक) को एक–एक करोड़ रुपये प्रदान किया गया।

7. 137 राज्य, राष्ट्रीय तथा 40 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

8. राष्ट्रीय सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर बालक/बालिका चौम्पियनशिप में भाग लेने वाली 64 प्रदेशीय टीमों को विशेष प्रशिक्षण शिविर की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें 1770 खिलाड़ी लाभान्वित ।

हर हाथ को मिले काम

श्रम एवं सेवायोजन

1. बेहतर औद्योगिक वातावरण सृजन हेतु राज्य में 15 श्रम अधिनियमों मे संशोधन।
2. छोटे/लघु उद्योगों को कारखाना अधिनियम तथा संविदा श्रम अधिनियम से मुक्ति।
3. दुकान एवं कारखानों में महिला कर्मकारों को रात्रि में काम करने की अनुमति।
4. नवीन निरीक्षण प्रणाली एवं स्व–प्रमाणन योजना लागू।
5. स्व–प्रमाणन योजना में प्रतिष्ठानों का पांच वर्ष में एक बार निरीक्षण की व्यवस्था लागू।
6. ब्वायलरों के तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की अधिसूचना निर्गत।

- बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान की 119 अनुसंशाओं में से 118 अनुशंसा लागू।

- स्वनियोजित कर्मकार हेतु आय की ऊपरी अधिकतम सीमा अधिसूचित।
- असंगठित कर्मकार हेतु कृषि योग्य भूमि की ऊपरी अधिकतम सीमा अधिसूचित।

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु पंजीयन कोड व्यवस्था लागू।

- असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण हेतु श्रम विभाग, पंचायती राज संस्था तथा नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत प्राधिकृत।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिये सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 22351 छात्रों को धनराशि रू0 96,04,590/– छात्रवृत्ति ।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामान्य बीमारियों के इलाज हेतु रू0 3,000/– वार्षिक सहायता।
- उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित पांच योजनाओं के अन्तर्गत 948 लाभार्थियों को कुल 70.00 लाख रुपए की धनराशि।

- 596 रोजगार मेले आयोजित रोजगार के लिए 57768 अभ्यर्थी चयनित।

- बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर हेतु sewayojan.up.nic.in वेबपोर्टल का विकास /ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा।
- सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को सेवायोजन वेबपोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था।

- 2203 कैरियर काउन्सिलिंग शिविर आयोजित एवं 2,58,559 अभ्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग।

- नई औषधि क्रय नीति जारी। घातक रोगों (कैन्सर हृदय रोग गुर्दा, लीवर आदि) हेतु महँगी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित।
- फिरोजाबाद एवं गोरखपुर में 30 बेड का मॉडल डिस्पेरन्सरी कम डायग्नोस्टिक सेन्टर, (एम0डी0सी0सी0) उन्नाव, मथुरा तथा मुरादाबाद में 30 बेड का चिकित्सालय एवं 13 जनपदों में 18 नये क0रा0बी0 औषधालय खोले जाने का निर्णय।

कर–प्रक्रिया का सरलीकरण, राजस्व में वृद्धि

वाणिज्य कर

- प्रदेश में जी0एस0टी0 (Goods and Service Tax) के रूप में कर संग्रहण की अत्यन्त सरल एवं पारदर्शी कर प्रणाली लागू की गयी।
- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा लगाये जा रहे 8 करों को समाप्त कर केवल एक कर लागू किया गया।
- आम उपभोक्ता के हित में खाद्यान्न व दलहन को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया जिससे राज्य सरकार पर रु0 700 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आया।
- किसानों के कल्याण हेतु Agriculture Equipment को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया एवं रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर 18% से घटाकर 5% की भारी कमी की गयी।
- दैनिक उपभोग की 400 से अधिक वस्तुएं, जिनमें घी, तेल, मसाले, जूते, चप्पल, साबुन व डिटर्जेंट आदि सम्मिलित हैं, पर कर की दर कम की गयी।
- व्यापारी हित में पंजीयन की सीमा रु0 5 लाख से बढ़ाकर रु0 20 लाख की गयी।
- पंजीयन की पूर्णतः पारदर्शी ऑन–लाइन व्यवस्था, जिसमें 3 दिन के अन्दर स्वत–पंजीयन का प्रावधान।
- रु0 1 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए समाधान योजना।
- कर आधार बढ़ाने हेतु रु0 5 लाख से अधिक नये व्यापारियों का पंजीकरण का रिकार्ड।

वाणिज्य कर राजस्व में माह जनवरी 2018 तक रु0 46500 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गयी जो गत वर्ष की तुलना में रु0 6200 करोड़ अधिक अर्थात **15.35 प्रतिशत अधिक** है। यह विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक है।

सचल–दल इकाईयों की कार्य प्रणाली को परिणामपरक एवं पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश के 41 प्रवेश मार्गों पर आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification Device) की अवस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

ऋण मोचन का नया आयाम

संस्थागत वित्त

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत 714 करोड़ रूपये व्यय कर 18694 लोग लाभान्वित।

- लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना लागू।
- दिनांक 31 मार्च, 2016 तक एन0पी0ए0 घोषित खातों के संबंध में सहकारी बैंकों हेतु एन0पी0ए0 समाधान योजना लागू ।
- प्रदेश में व्यावसायिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की 16734 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।
- जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल बैंक के नये 25 बैंकिंग आउटलेट खोले गये

जन जन तक सिनेमा की पहुंच

मनोरंजन कर

- प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमाडल करवाने, असेवित 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी। सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के 18 स्क्रीन के निर्माण के आवेदन पत्र प्राप्त। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 08 स्क्रीन के निर्माण की अनुमति/स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2018

- उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 में (पांचवां संशोधन कर) को लाईसेंसिंग प्राक्रिया को सरलीकृत करते हुए ऑनलाईन किया जा रहा है। स्थायी वीडियो सिनेमा को एक बार में अधिकतम 03 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष हेतु लाईसेंस स्वीकृत/नवीनीकृत किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था की जा रही है, जिससे व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त हो सके।

जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों के टिकट के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति नीति-

- प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं यथा अन्तर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, टी–20 मैच एवं आई.पी.एल के टी0–20 मैच पर मनोरंजन कर अधिरोपित किये जाने का निर्णय।

पारदर्शिता से बढ़ी आय

भूतत्व एवं खनिकर्म

- समस्त उपखनिजों के परिहार ई निविदा/ई नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से किये जाने के प्राविधान।
- बालू/मोरंग के 825 क्षेत्रों पर ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें से 346 क्षेत्रों पर लेटर आफ इन्टेंट जारी किये गये। 346 क्षेत्रों में से वर्तमान में 126 क्षेत्रों पर खनन कार्य प्रारम्भ।
- इमारती पत्थर के क्षेत्रों को ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश।
- अनधिकृत खनन के लिए अर्थदण्ड एवं कारावास दोनों का प्राविधान।
- उपखनिजों के परिवहन हेतु मुद्रित अभिवहन प्रपत्र एम0एम0 11 के स्थान पर ई अभिवहन प्रपत्र एम0एम0 11 लागू।
- सेटेलाइट इमेज के माध्यम से पट्टा क्षेत्र से बाहर किये गये खनन पर नजर।
- अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु माह जनवरी–2018 तक प्रदेश में 15369 छापे मारकर, रू0 3668.50 लाख की वसूली।
- जिलों में खनिज फाउण्डेशन का गठन।

ई–निविदा सह ई नीलामी के फलस्वरूप माह जनवरी–2018 तक खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व रू 2248.04 करोड़, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व रू0 1200.79 करोड़ था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में रू 1047.25 करोड़ अधिक राजस्व की प्राप्ति। यह गत वर्ष से 87 प्रतिशत अधिक है।

खातेदारों के लिए सुगम तकनीक

राजस्व

- ✶ एन्टी–भूमफिया अभियान के अन्तर्गत कुल 1,56,957 शिकायतों के सापेक्ष 1,49,788 शिकायतों का निस्तारण। कुल 46233 हे0 क्षेत्रफल भूमि अतिक्रमणमुक्त।
- ✶ अभियान के अन्तर्गत 17522 राजस्व वाद, 573 सिविल वाद तथा 2569 एफ0आई0आर0 दर्ज।
- ✶ अभियान के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया में संहिता के अन्तर्गत 604, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 127, गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 43, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत 247 व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 928 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही।
- ✶ 208 अभियुक्त जेल में निरूद्ध।

भू–मानचित्रों का डिजिटाइजेशन

56726 ग्रामों का मैप डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण। अवशेष 1,03,087 राजस्व ग्रामों की कुल 1,17,050 मैपशीट्स का सत्यापन।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- ✶ भूमिहीन मजदूरों और निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लोकार्पण।
- ✶ नयी योजना के अन्तर्गत 13,181 लोग लाभान्वित।

कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना

कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में कुल धनराशि रूपये 172 करोड़ अवमुक्त, जिससे कृषक बीमा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 3440 लाभार्थी लाभान्वित।

कृषि भूमि/पट्टा आवंटन

- ✶ कृषि भूमि आवंटन के अन्तर्गत 1633 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 1837 हे0 भूमि का आवंटन, जो लक्ष्य का 112.54 प्रतिशत है।
- ✶ आवास आवंटन के अन्तर्गत 20120 परिवारों में से 20543 परिवारों को आवास स्थल आवंटित, 102.66 प्रतिशत है।
- ✶ मत्स्य पालन के लिए 8134 हे0 तालाबों के लक्ष्य सापेक्ष 6857 हे0 का आवंटन, जो लक्ष्य का 84.30 प्रतिशत है।
- ✶ वृक्षारोपण पट्टों के अन्तर्गत 457 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 555 हे0 का आवंटन, जो लक्ष्य का 121.69 प्रतिशत है।
- ✶ कुम्हारी कला के लिए 1184 स्थलों के सापेक्ष 1204 स्थलों का आवंटन, जो लक्ष्य का 101.69 प्रतिशत है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस

जन समस्याओं के निराकरण के लिये प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है जिसमें विगत एक वर्ष में कुल 563548 शिकायतें जिसके सापेक्ष कुल 558943 जन शिकायतों का निस्तारण।

प्रकृति से प्यार

वन एवं वन्य जीव

वर्ष 2015 की स्थिति के सापेक्ष प्रदेश में 218 वर्ग कि0मी0 वनावरण तथा 398 वर्ग कि0मी0 वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 14,679 वर्ग कि0मी0 (6.09 प्रतिशत) वनावरण तथा 7,442 वर्ग कि0 मी0 (3.09 प्रतिशत) वृक्षावरण है। इस प्रकार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 22,121 वर्ग कि0मी0 (9.18 प्रतिशत भाग) वनावरण व वृक्षावरण से आच्छादित है।

- 62 जनपदों में वन भूमि के बाहर स्थित आम, नीम, साल महुआ व खैर प्रजातियों को छोड़कर अन्य समस्त वृक्ष प्रजातियों के कटान एवं ढुलान पर सभी प्रतिबंध हटाये गये।

- कृषकों को अपने खेत की मेड़ पर पंक्ति वृक्षारोपण एवं कृषि भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण के लिए अनुदान की व्यवस्था। 50 प्रतिशत लाभार्थी छोटे एवं सीमान्त कृषक, जिनमें न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलायें। मेड़ पर पंक्ति वृक्षारोपण में प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 पौध तथा ऐसे लाभार्थी को प्रति पौध रोपण में व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू0 35/– प्रति पौध जो भी कम हो, का अनुदान।

- कृषि भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण (कृषि जोत/पूरे खेत में रोपण) के लिए अधिकतम 500 पौध प्रति हेक्टेयर तथा ऐसे लाभार्थी को पौध रोपण में व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू0 14,000/– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो, का अनुदान।

- प्रदेश के 20 ईको पर्यटन स्थल के विकास की वन विभाग व पर्यटन विभाग के मध्य हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर ।

- एण्टी भू माफिया प्रथम बार अभियान चलाकर 1870 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि खाली कराई गई।

- तेंदू पत्ता संग्रहण में वन क्षेत्र के निकट ग्राम वासियों को संग्रहण के लिए रू0 23.55 करोड़ वितरित।

- .30 करोड़ पौध रोपण लक्ष्य के सापेक्ष 4.52 करोड़ पौधों का रोपण।

यूपी नहीं देखा तो इण्डिया नहीं देखा

पर्यटन

- ☆ मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ☆ स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट के अन्तर्गत अयोध्या में राम कथा गैलरी, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट एवं अन्य मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के कार्य एवं श्रृंगवेरपुर (जनपद–इलाहाबाद) में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, घाट एवं अन्य मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के कार्य तथा चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग पर कवर्ड शेड, मध्य प्रदेश एवं रामघाट के मध्य फुट ओवरब्रिज, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, रामायण गैलरी एवं अन्य मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के कार्यों हेतु भारत सरकार से रू0 202.75 करोड़ की धनराशि से सभी स्थलों पर कार्य प्रारम्भ।
- ☆ स्वदेश दर्शन स्कीम के बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती में साउण्ड एण्ड लाईट शो एवं अन्य मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि कार्यों हेतु भारत सरकार से रू0 100.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करायी गई। सभी स्थलों पर कार्य प्रारम्भ।
- ☆ स्वदेश दर्शन स्कीम के हेरिटेज सर्किट एवं स्पिरीचुअल सर्किट–1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु भारत सरकार से रू0 180.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृति करायी गई। सभी स्थलों पर कार्य प्रारम्भ।
- ☆ प्रसाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी में पर्यटन विकास कार्यों के लिये रू0 92.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करायी गई।
- ☆ प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत मथुरा हेतु रू0 24.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृति।
- ☆ ब्रज के सम्पूर्ण एवं समग्र विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना।
- ☆ विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ उ0प्र0 प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना रू0

371.43 करोड़ का ऐग्रीमेन्ट। इस योजना के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट के समेकित पर्यटन विकास हेतु लगभग रू0 1000.00 करोड़ की योजना तैयार कराई जा रही है।

- ☆ ईको टूरिज्म एवं वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दुधवा, कतरनिया, चन्द्रप्रभा, पटना पक्षी विहार, बखिरा पक्षी विहार, कुकरैल, नवाबगंज पक्षी विहार, सोहगीबरवा पक्षी विहार आदि का विकास।
- ☆ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान।
- ☆ सूरज कुण्ड मेला–2018 में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रथम बार थीम स्टेट के रूप में प्रतिभाग। रामायण परिपथ, कृष्ण/ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ, वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज्म परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ तथा जैन परिपथ का चिह्नांकन।
- ☆ पर्यटन के समुचित विकास एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने हेतु पर्यटन नीति–2018 प्रख्यापित।
- ☆ वन स्टाप ट्रेवल सल्यूशन पोर्टल की व्यवस्था।
- ☆ उ0प्र0 की ब्राण्डिंग के लिए "यू0पी0 नहीं देखा, तो इण्डिया नहीं देखा" की टैग लाइन ब्राण्डिंग।
- ☆ कुम्भ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित–प्रसारित कराने हेतु प्रथम बार पर्यटन विभाग द्वारा कुम्भ–2019 का लोगो जारी। उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सभी विज्ञापनों, राजकीय पत्राचारों एवं प्रचार के अन्य माध्यमों में लोगो का प्रयोग।
- ☆ इन्वेस्टर्स समिट मे 58 एम0ओ0यू0 के माध्यम से रू0 14803.79 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्र में निवेश हेतु प्राप्त।
- ☆ वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को "पावन पथ" के नाम से विकसित किया जा रहा है।
- ☆ प्रदेश के विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकाप्टर–राइड की सुविधा उपलब्ध।
- ☆ गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में जलक्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 59.00 करोड़ की लागत से वाटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण इसके साथ ही पूर्व निर्मित जेटी के जीर्णोद्धार हेतु रू0 77.94 लाख की योजना स्वीकृत।

अपनी संस्कृति को सम्मान

संस्कृति विभाग

- दक्षिण कोरिया में आयोजित ''अयोध्या महोत्सव'' अयोध्या में सांस्कृतिक दल का प्रतिभाग।
- नवम्बर, 2017 में कुरूक्षेत्र, हरियाणा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ''स्टेट पार्टनर'' के रूप में प्रतिभाग।
- सूरजकुण्ड, हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेलें में उत्तर प्रदेश राज्य 'थीम स्टेट' के रूप में चयनित।
- अयोध्या में आयोजित ''दीपोत्सव'' में तीन देशों की रामलीला के साथ–साथ शोभा यात्रा में 700 कलाकारों की सहभागिता।
- अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के अन्तर्गत मेघालय, अरूणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के मध्य साझेदारी।
- अयोध्या शोध संस्थान द्वारा ''राम की वैश्विक यात्रा'', ''जनजाति में राम'' के प्रकाशन के साथ–साथ इन्डोनेशिया में रामलीला का मंचन।
- गोरखपुर में रू0 50.00 करोड़ की लागत के प्रेक्षागृह निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना।
- कुसुम सरोवर, मथुरा, चुनार किला, मिर्जापुर, रोशनुद्दौला कोठी, कोठी दर्शन विलास,कोठी गुलिस्ताने इरम, लखनऊ का वृहद् अनुरक्षण कार्य।
- स्मारक छतर मंजिल का विशेष अनुरक्षण कार्य।

पारदर्शिता के प्रतिमान

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन

मुख्यालय से लेकर उप निबन्धक कार्यालयों तक समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बी.ए.एस.) के माध्यम से उपस्थिति अंकित किये जाने की व्यवस्था लागू।

ऑनलाइन आधार आधारित भार मुक्त प्रमाण–पत्र बारह साला प्रणाली लागू। विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था लागू।

परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु गत 10 वर्षों की मूल्यांकन सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध।

परम्परागत कोर्टफीस (टिकट एवं स्टाम्पों) के साथ–साथ स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से ई–कोर्ट फीस की वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गयी।

दिनांक 05–12–2017 से प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में विलेखों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण एवं निबन्धन की व्यवस्था लागू ।

श्रद्धा को नमन धर्मार्थ कार्य

कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान

मा. मुख्यमंत्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रियों को प्रदान किये जाने वाले यात्रा अनुदान की राशि रु. पचास हजार से बढ़ाकर रु. एक लाख किये जाने की घोषणा की गयी थीं जिसके अनुपालन में राशि रु. एक लाख किये जाने का आदेश जारी। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु.–550 लाख का आय–व्यय का प्राविधान है।

प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनके द्वारा लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा की जाती है, को रुपये 10 हजार प्रति यात्री की दर से यात्रा अनुदान दिया जाता हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु.–10 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान हैं।

जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में

पर्यटन के दृष्टिकोण से जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना प्रस्तावित। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में रु.–400 लाख उपलब्ध।

कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण

कैलाश मानसरोवर भवन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना अन्तर्गत 9000 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया है, जिसकी कीमत रु. 50.40 करोड़ हैं। मा. मुख्यमंत्री द्वारा जनपद गाजियाबाद के इन्दिरापुरम में दिनांक 31.08.2017 को कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास किया गया हैं। कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा रु. 6098.94 लाख की लागत अनुमोदित की गयी है।

जनपद वाराणसी में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना

धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना किये जाने का निर्णय। जिसमें वैदिक साहित्य एवं वैदिक ज्ञान–विज्ञान, दर्शन परम्परा आदि विषयों का अध्ययन–अध्यापन कराया जाएगा। वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रु.–803.83 लाख का आगणन अनुमोदित।

बढ़ती रहे कारीगरी

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी–2017 प्रख्यापित। पॉलिसी के अन्तर्गत रू0 7436 करोड़ के निवेश के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
- बुनकरों के कल्याण तथा हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अब तक रू0 345.59 करोड़ की धनराशि व्यय, जो गत वर्ष की तुलना में **7 गुना से भी अधिक** है।
- मुबारकपुर आजमगढ़ 158 दुकानों से युक्त विपणन केन्द्र की स्थापना।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना मा0 मंत्रि परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत। 03 हथकरघा बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिवस (24 जनवरी, 2018) के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये।
- महात्मा गाँधी हथकरघा बुनकर बीमा योजनान्तर्गत 1474 दावों का निस्तारण कराकर रू0 8 करोड़ 84 लाख की धनराशि बुनकरों के आश्रितों को उपलब्ध करायी गयी।
- पावरलूम कामगारों हेतु संचालित समूह बीमा योजनान्तर्गत 148 दावों का निस्तारण कराकर रू0 87.20 लाख की धनराशि आश्रितों को उपलब्ध करायी गयी।
- पावरलूम उद्योग विकास योजना के तहत लगभग 1670 नये सेमी–आटोमेटिक पावरलूम स्थापित।
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्लस्टर अप्रोच योजना में 9142 हथकरघा बुनकर लाभान्वित।

स्वावलंबन को बल

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी संस्थाओं को बिक्री के आधार पर रिबेट दिये जाने की व्यवस्था थी, जिसके स्थान पर उत्पादन आधारित रिबेट (पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत की दर से उत्पादन पर सहायता दी जायेगी जिसका 33 प्रतिशत संस्था को उत्पादन के आधार पर, 33 प्रतिशत विपणन संवर्धन हेतु तथा 34 प्रतिशत संस्था में कार्यरत कत्तिन/बुनकरों को सीधे उनके खाते में दिया जायेगा।

परम्परागत चर्खों के स्थान पर सोलर चर्खों को संचालित किये जाने का निर्णय। कतकरों एवं बुनकरों को सीधे अधिक लाभ मिलेगा।

वर्ष 2017–18 में 4219 इकाइयों को स्थापित कराये जाने के लक्ष्य के अन्तर्गत अब तक कुल 10600 आवेदन पत्र बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये, जिसके सापेक्ष 2293 आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत करके रू0 11436.00 लाख का ऋण वितरित। इस कारण 12540 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

वार्षिक लक्ष्य 840 इकाइयों के सापेक्ष कुल 11923 आवेदन पत्रों के सापेक्ष प्राप्त, 4011 लाभार्थियों का चयन करते हुए वित्त पोषण हेतु बैंकों को भेजे गये। इनमें से अब तक (माह फरवरी 2018 तक) 949 लाभार्थियों को धनराशि रू0 5249.40 लाख का ऋण वितरित कराते हुए कुल 20950 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

आई.टी. से रोजगार

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स

- उ0प्र0 शासन के ई–टेण्डर पोर्टल से रू 1.30 लाख करोड़ मूल्य की 1,48,768 निविदायें आमंत्रित।
- ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग, NEFT/RTGS से किये जाने की व्यवस्था कार्यान्वित।
- शत–प्रतिशत ई–टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित स्मार्ट सिटी समिट' में प्रदेश पुरस्कृत।
- मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में रू0 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना प्रगति पर।
- स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए 10 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत। प्रदेश के विभिन्न नगरों में 13 इन्क्यूबेटर्स प्रस्तावित।
- इन इन्क्यूबेटर्स में 100 से अधिक स्टार्ट–अप इकाइयाँ कार्यरत।
- 30 एकड़ भू–क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना। 500 प्रशिक्षाणार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र–1 कार्यरत। छात्रों का प्रशिक्षण प्रारम्भ। 1000 प्रशिक्षाणार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र–2 निर्माणाधीन।
- आईटी– 03 भवन का निर्माण पूर्ण। लगभग 2000 सॉफ्टवेयर कर्मी, विकासकर्ता कार्यरत हैं। मार्च 2018 तक

500 सॉफ्टवेयर कर्मी और सम्मिलित हो जायेंगे।

- ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक–6 में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना। इस क्लस्टर में चीन तथा ताईवान की कम्पनियों द्वारा लगभग रू 3000 करोड़ का निवेश होगा।
- प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 01 अप्रैल 2018 से ई–आफिस प्रणाली लागू करने का लक्ष्य।
- भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को डिजिटल पेमेन्ट हेतु 312 करोड़ ट्रॉजेक्शन का लक्ष्य निर्धारित दिसम्बर 2017 तक लगभग 110 करोड़ डिजिटल ट्रॉजेक्शन्स।
- समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लाक मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों में स्वान 2.0 के अन्तर्गत नवीनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य।
- समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 01 जन सेवा केन्द्र स्थापित करने के क्रम में अब तक 75,000 से अधिक जन सेवा केन्द्र राज्य् में स्थापित।
- राज्य में स्थापित 59,000 जन सेवा केन्द्रों को भीम एप से जोड़ा गया।
- प्रदेश में अब तक 2,59,117 डिजिटल लॉकर खोले जा चुके है।
- ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही एन.आई.सी. के माध्यम से प्रक्रियाधीन।
- ई–डिस्ट्रिक्टि पोर्टल से प्रदान की जा रही सेवा आर.ए.एस. प्रणाली से इंटीग्रेट की गयी।

सबको पहुंचे सही बात

सूचना एवं जनसम्पर्क

- विभाग द्वारा दीनदयाल जन्मशती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अब तक मुख्यालय स्तर पर पर 21, जिला स्तर पर 75 तथा ब्लाक स्तर पर 851 प्रदर्शनियां लगायी गयी। प्रदेश को दीनदयाल जी के उदगारों एवं उनके विचारों से परिचित कराने के लिए पं0 दीनदयाल वांग्मय (15 खण्डों में) के 7 हजार सेट का वितरण प्रदेश के अनेक शिक्षण संस्थानों, विश्व–विद्यालयों, पुस्तकालयों आदि में सुनिश्चित कराया गया।

- स्वराज्य की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 101 जयंती 30 दिसम्बर 2017 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर देश भर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बुलाकर सम्मानित किया गया और लोकमान्य के विचारों एवं जीवन दर्शन पर आधारित लोकमान्य तिलक स्मारिका का प्रकाशन कर उसकी 5 हजार प्रतियां कार्यक्रम में विभाग द्वारा वितरित करायी गयी।

- उ0प्र0 राज्य के गठन की स्मृति में दिनांक 24, 25 एवं 26 जनवरी को तीन दिवसीय यू0पी0 दिवस कार्यक्रम का प्रथम बार भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत उल्लेखनीय योगदान करने वाले महापुरूषों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के नव निर्माण हेतु रू0 25 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं

1. आकर्षक सोशल मीडिया मैगजीन 'ई–सन्देश' लॉन्च।
2. न्यूज वेबसाइट की तर्ज पर सूचना विभाग की अद्यतन वेबसाइट का निर्माण।
3. प. दीन दीयाल उपाध्याय जन्मशती के अवसर पर 900 से अधिक प्रदर्शिनियों का आयोजन तथा 7 हजार सेट वांगमय का वितरण।
4. सूचना विभाग के तत्वावधान में प्रथम उ0प्र0 दिवस का आयोजन।

लोकार्पण भी किया गया।

- राज्य में पूंजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए आयोजित इन्वेस्टर्स समिट–2018 दिनांक 21–22 फरवरी को लखनऊ में समपन्न हुआ। सूचना विभाग द्वारा समिट का अभूतपूर्व देशव्यापी प्रचार–प्रसार किया गया। मीडिया एण्ड इण्टरटेनमेण्ट सेशन के अन्तर्गत प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 एम0ओ0यू0 का हस्ताक्षरित।

- सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन प्रभाग द्वारा अब तक प्रिंट मीडिया में 220 सजावटी विज्ञापन और 8500 वर्गीकृत विज्ञापन जारी किए गये तथा 63115 होर्डिंग्स, स्टैण्डी, यूनीपोल आदि स्थापित किये गये। साथ ही, 368 एल0ई0डी0 वीडियो वैन, 81 डिस्प्ले बोर्ड एवं 607 स्क्रीन्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्य कराया गया।

- सरकार की विकासपरक योजनाओं/कार्यक्रमों को सुग्राह्य रूप से प्रचारित करने के लिए सामयिक मासिक पत्रिकाओं यथा हिन्दी में ''उ0प्र0 संदेश'' उर्दू में ''नया दौर'' का प्रकाशन किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य की सेवा के लिए ''उ0प्र0 मासिक'' का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ ''वार्षिकी उ0प्र0'' का प्रकाशन दोनों प्रमुख भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में किया जा रहा है।

- इनके अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों जैसे–सूचना डायरी, निदर्शनी, विशेषांक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी एवं उनके जीवन दर्शन पर आधारित वांग्मय, फसली ऋण मोचन प्रमाण पत्र, सरकार के 100 दिन एवं छह माह के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों की पुस्तिकाएं, प्रमाण पत्र, पोस्टर आदि का भी प्रकाशन किया गया है। गीत एवं नाट्य शाखा द्वारा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार के लिए 12700 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी तरह प्रदर्शनी शाखा द्वारा सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

- सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के मध्य त्वरित प्रचार हेतु मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब की स्थापना की गई तथा सभी सूचनाओं, चित्रों आदि को न्यूनतम समय में मीडिया तक पहुंचाने एवं विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाईट information.up.nic.in का पुनः निर्माण किया गया।

- यू0पी0 दिवस के अवसर पर विभाग की साप्ताहिक सोशल मीडिया मैगजीन ई–संदेश को लोकार्पित किया गया। इसे सूचना विभाग

की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

- प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पालिसी–2018 लागू की गई है। प्रदेश के अन्दर हिन्दी भाषा एवं उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा एवं देश की किसी भी भाषा में उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्मों को भी अनुदान दिए जाने का प्राविधान किया गया है। अनुदान की अधिकतम सीमा 3 करोड़ 75 लाख रूपये तक है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे एवं सत्यजीत रे, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता में अध्ययनरत उ0प्र0 के 10–10 छात्रों को प्रतिवर्ष 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

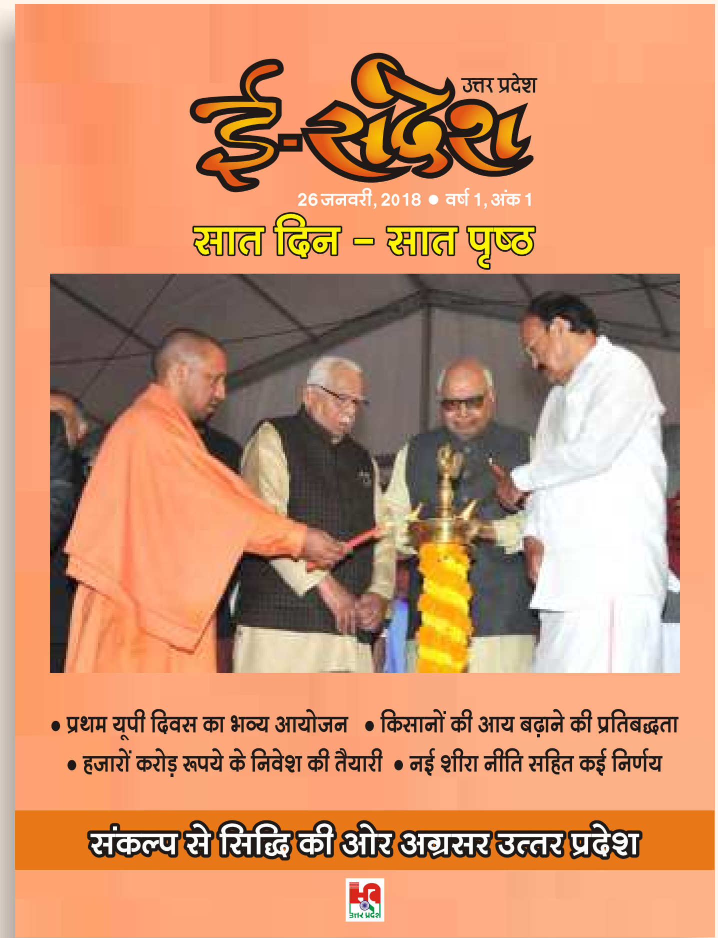

19 मार्च 2017 से अद्यतन हिन्दी में 4314 तथा उर्दू में 1895 प्रेस नोट जारी

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा 920 हिन्दी प्रेस नोट, 504 उर्दू प्रेस नोट तथा 275 अंग्रेजी प्रेस नोट जारी

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार के लिए 12700 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

सरकार के कार्यक्रमों नीतियों एवं प्रचार प्रसार हेतु 5000 फोटो और 1300 वीडियो क्लिपिंग्स जारी।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल

- पिछले एक वर्ष में 84882 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 1038 गहरी बोरिंग, 4480 मध्यम गहरी बोरिंग एवं 100 सामूहिक नलकूपों का निर्माण करके 1.68 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा व औषधि आदि क्षेत्र की 105 शोध परियोजनाओं हेतु रू0 4.00 करोड़ का वित्त पोषण।
- जनपद सोनभद्र में 02 खनन क्षेत्रो का उपग्रहीय आंकड़ों के माध्यम से चिह्नांकन कर सजरा स्तर पर डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया। बाढ़ प्रभावित जनपदों का उपग्रहीय आधारित मानचित्र तैयार कर जिला प्रशासन को 48 घण्टे में बाढ़ राहत हेतु उपलब्ध कराया गया।

ग्रामीण अभियन्त्रण

- विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल विकास निधि, पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, बार्डर एरिया एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 3624 संपर्क मार्गों का निर्माण।
- सांसद निधि, विधायक निधि,पूर्वांचल विकास निधि, बुन्दलेखण्ड विकास निधि,जिला योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 1284 भवनों का निर्माण कार्य कराया गया।

सचिवालय प्रशासन

- उत्तर प्रदेश सचिवालय में 01 अक्टूबर, 2017 से ई–आफिस की व्यवस्था 20 विभागों में लागू। शीघ्र ही शेष विभागों में ई–आफिस व्यवस्था लागू कर ली जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों/ कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की बायो–मैट्रिक एवं आधार पर आधारित प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय।

न्याय

- प्रदेश के 13 जनपदों– मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी में वाणिज्य विवादों के निस्तारण हेतु कामर्शियल कोर्ट्स का गठन किया गया है।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश के 13 जनपदों में गठित कामर्शियल कोर्ट के संचालन हेतु रू0 1.00 करोड़ की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

चकबन्दी

- 2,60,111 चकबन्दी वादों का निस्तारण किया गया।
- प्रदेश के 1,01,171 राजस्व ग्राम प्रथम चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया में लिये गये जिसमें से 1,00,059 ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण करायी जा चुकी है। इसी प्रकार द्वितीय चक्र की कुल 27,166 राजस्व ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के सापेक्ष 23,781 राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करायी जा चुकी है।
- 1 अप्रैल 2017 से अब तक 296 ग्रामों में नव प्रदिष्ट चकों पर सीमांकन/कब्जा दिलाया जा चुका है।

होमगार्डस

- ''नमामि गंगे जागृति यात्रा'' के अन्तर्गत बिजनौर से बलिया तक जन जागरण अभियान में 25 जिलों में 27 जन–जागरण गोष्ठियों का आयोजन हुआ।
- 'लक्ष वृक्ष अभियान' के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में होमगार्ड्स जवानों के माध्यम से लगभग एक लाख से अधिक वृक्ष रोपित।

रेशम विकास

- 10 राजकीय रेशम फार्मों पर सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधा से सिंचन क्षमता में वृद्धि। 60 राजकीय रेशम फार्मों पर सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था।
- फतेहपुर में एरी रेशम बीजागम में 1.50 लाख डी.एफ.एल्स. कीटाण्ड उत्पादन का कार्य प्रारम्भ। उन्नत प्रजाति के शहतूत वृक्षारोपण हेतु रेशम फार्मों की 100 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण प्रारम्भ।
- उत्कृष्ट रेशम कोया उत्पादन करने वाले तथा धागाकरण 50 उद्यमियों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार। 373 रेशम कीटपालकों/कोया उत्पादकों को नवीन तकनीक में अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण।

राजनैतिक पेंशन

- प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान राशि रू० 15,176 में प्रतिमाह रू० 5,000 की वृद्धि करते हुये रू० 20,176 प्रतिमाह किया गया है।
- आपातकाल अवधि में (दिनांक 26–06–1975 से 21–03–1977 तक) में मीसा/डी०आई०आर० में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक 6 माह पर जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया के स्थान पर राजकीय पेंशनर्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में अपनायी जा रही सामान्य व्यवस्था के समान ही लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि भुगतान किये जाने हेतु वर्ष में 1 बार जीवित रहने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

INVESTORS
कुम्भ
आरक्षित

UP
POWERING NEW INDIA

INVESTORS SUMMIT 2018

सबका साथ–सबका विकास

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, 257–गोलागंज, लखनऊ